My Notes....

राष्ट्रीय

'उड़ान' नामक आरसीएस के तहत प्रथम उड़ान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 अप्रैल, 2017 को 'उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) नामक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत शिमला-दिल्लीं रूट पर प्रथम उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 'उड़ान' के तहत कडप्पा-हैदराबाद और नांदेड़-हैदराबाद क्षेत्रों पर भी प्रथम उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन हवाई अड्डों को हवाई कनेक्टिविटी सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वर्तमान में या तो हवाई सेवा बिल्कुल भी उपलब्धी नहीं है या बेहद कम संख्या में उपलब्ध है।

UDAN की खास बातें

1. इस स्कीम में 45 ऐसे एयरपोर्ट्स जो सेवा में नहीं हैं, उन्हें एयर नेटवर्क में कनेक्ट किया गया है।
2. इस स्कीम में 5 ऑपरेटर्स का चयन हुआ है- एयर इंडिया की सब्सिडियरी अलाइड सर्विसेज, स्पाइसजेट, एयर डेक्कन, एयर ओडिशा, टर्बो मेघा।
3. टियर-2 और टियर-3 शहरों के 13 एयरपोर्ट्स, जहां ज्यादा फ्लाइट्स नहीं चलती थीं वहां अब अधिक फ्लाइट्स होंगी।
4. सिविल सेक्रटरी आरएन चौबे ने बताया, हर फ्लाइट में 50 प्रतिशत सीट्स 2,500 रुपए एक घंटे के रेट पर होंगी।

क्या है?

1. क्षेत्रीय दृष्टि से महत्वयपूर्ण शहरों में रहने वाले लोगों को हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए मंत्रालय ने अक्टूडबर, 2016 में 'उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) नामक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) शुरू की थी।
2. विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने और हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद उड़ान योजना तैयार की गई थी। बाजार आधारित व्यवस्था के जरिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली यह योजना विश्वी भर में अपनी तरह की पहली स्कीम है।
3. उड़ान योजना राष्ट्री य नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) का एक अहम हिस्सा है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 जून, 2016 को जारी की थी।

भारत का पहला 'अर्बन पॉड'

भारत का पहला 'अर्बन पॉड' होटल मुंबई के अंधेरी में खुल गया है। जापान में पर्यटकों के लिए शुरू हुए कम दामों में महंगे होटलों जैसी सुविधा दिलाने वाले अर्बन पॉड में दो लोगों तक के ठहरने की व्यवस्था रहती है। इन पॉड (कमरों) में लग्जरी का पूरा ध्यान रखते हुए हर चीज मुहैया कराई जाती है, जिसके लिए बेहद कम दाम वसूले जाते हैं। इसमें खाना और नाश्ता जुड़ा होता है। ये सब मौजूदः प्लाज्मा टीवी, एसी, चार्जिंग प्वाइंट, ड्रेसर्स, सेफ्टी लाकर, पढ़ने के लिए विशेष रोशनी, फ्री वाईफाई। सफर पर निकली अकेली महिलाओं के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। अंधेरी स्थित इस शैली के होटल में अकेली महिलाओं के लिए विशेष पॉड की व्यवस्था है, इसमें सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है।

क्या है?

1. देश का पहला अर्बन पॉड होटल मुंबई के अंधेरी में खुला।
2. जापान की तर्ज पर बने इस होटल में लग्जरी का विशेष ध्यान।
3. 1800-3200 रुपये में आलीशान कमरे
4. 140 पॉड कमरे हैं इस होटल में।
5. 60 सीटर कैफे नाश्ते के लिए।

देश का पहला 'किताबों वाला गांव'

महाराष्ट्र के सतारा जिले का भीलर गांव अपनी स्ट्रॉबेरी के लिए काफी मशहूर है। अब यह किताबों के कारण भी लोकप्रिय होने जा रहा है, क्योंकि इसे देश के पहले 'किताबों वाला गांव' (पुस्तकांचं गांव) का तमगा मिलने वाला है। यह अवधारणा ब्रिटेन के वेल्स शहर के हे-ऑन-वे से प्रभावित है। हे-ऑन-वे अपने पुस्तक भंडारों और साहित्य महोत्सवों के लिए जाना जाता है।

क्या है?

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

1. भीलर गांव प्राकृतिक रूप से खूबसूरत पंचगनी पहाड़ी क्षेत्र के निकट स्थित है। इसे किताबों वाला गांव बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस चार मई को इसका उद्घाटन करेंगे।
2. सूबे के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के नेतृत्व में इस परियोजना पर मराठी भाषा विभाग काम कर रहा है। गांव के आसपास किताबें पढ़ने के लिए 25 जगहों को चुना गया है। यहां साहित्य, कविता, धर्म, महिला, बच्चों, इतिहास, पर्यावरण, लोक साहित्य, जीवन और आत्मकथा संबंधी किताबें होंगी।
3. इस गांव परिसर में करीब 15,000 किताबें (मराठी भाषा में) उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार ने मराठी भाषा दिवस पर 27 फरवरी, 2015 को इस तरह के 'किताब वाला गांव' और साहित्य उत्सव आयोजित करने की योजना की घोषणा की थी।
4. अब हम यह उन लोगों के लिए खोल रहे हैं, जिन्हें भाषा और साहित्य से प्रेम है। कोई भी अपनी पसंद की किताब चुन सकता है। जब तक चाहे पढ़ सकता है। बाद में दूसरों के पढ़ने के लिए उसे वहीं रख सकता है।

रूसा (आर.यू.एस.ए.) की शुरुआत

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 17 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा विकसित निधि एवं सुधार ट्रैकर की शुरुआत की गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है निधि एवं सुधार ट्रैकर रूसा (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan – RUSA) परियोजना की निगरानी करेगा। इसके जरिये किसी भी परियोजना के मंजूर होने से लेकर सफलतापूर्वक सम्पन्न होने तक के सभी चरणों की निगरानी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर, सुधार ट्रैकर राज्यों की उच्च शिक्षा नीतियों, योजनाओं एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के विवरण के रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य भी करेगा। वस्तुतः यह सुविधा देशभर में फैले हजारों विक्रेताओं के अलावा, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के उच्च शिक्षा हितधारकों और अन्य संस्थानिक व्यक्तियों के लिये उपलब्ध होगी।

प्रत्येक हितधारक की भूमिका और कार्यक्षमता के आधार पर उन्हें एप का इस्तेमाल करने के लिए सीमित/असीमित अधिकार प्रदान किये जाएंगे।

क्या है?

1. यह परियोजना अनुमोदन बोर्ड के आधार पर आवंटित निधि, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किश्त के आधार पर जारी निधि, संस्थानों के आधार पर मुख्य परियोजनाओं, नियुक्त विक्रेता एवं उनको किया गया भुगतान, राज्यों के अनुसार किये गए भुगतान एवं इनके संबंध में प्राप्त किसी भी प्रकार की टिप्पणी आदि की जानकारी को अपने अंदर सहेजकर रखेगा।
2. घटक (कम्पोनेंट) के अनुरूप विवरण, रूसा परियोजना में की जाने वाली निधि का व्यापक चित्र हमारे सामने पेश करता है। चाहे यह इक्विटी पहल के बुनियादी ढांचे का अनुदान हो।
3. यह एप हमें अनुमोदित निधि, जारी राशि, उपयोग की गई राशि पूरे किये गए काम का प्रतिशत आदि की जानकारी उपलब्ध कराएगी।
4. हितधारक केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी धन के बारे में बारीकी से पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकता है।
5. प्रत्येक पहल को एक अलग पहचान संख्या (आई.डी. नंबर) दिया गया है। इससे इस बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार कोई विचार पैदा हुआ और किन-किन चरणों से होते हुए उसका पूर्ण विकास हुआ।
6. इस एप का प्रभावशाली एवं दमदार डैशबोर्ड योजना की व्यापक तस्वीर और राज्यवार कार्यक्रम के अंतर्गत हुए प्रभाव के प्रदर्शन को दिखाता है।
7. यह एप भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना 'डिजिटल इंडिया' को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

इंडिया करप्शन स्टडी-2017 रिपोर्ट

देश के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उनकी सूची में कर्नाटक टॉप पर है। इस बात का खुलासा 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी-2017 रिपोर्ट में कहा गया है। सरकारी कामों को कराने के लिए दिए जाने वाले घूसों के आधार पर भ्रष्ट राज्यों की सूची तैयार की गई है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले राज्यों में कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और पंजाब का नंबर है। हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ सबसे कम भ्रष्टाचार वाले राज्यों की सूची में हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

क्या है?

1. नीति आयोग के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी-2017 रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं के लिए जनता को घूस देना पड़ा है। देश के 29 में से 20 राज्यों में किये गये सर्वे के आधार पर हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
2. रिपोर्ट में आकलन किया गया है कि 20 राज्यों के लोगों ने 10 सार्वजनिक सेवाओं के लिए 6,350 करोड़ रुपये की रिश्वत 2017 में दी। वर्ष 2005 में लोगों ने 20,500 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी। इस साल कराये गए अध्ययन में 53 फीसद लोगों ने रिश्वत देने की बात कबूल की थी।

कहां, कितने लोगों ने दी रिश्वत		
1.	कर्नाटक	77.0 फीसद
2.	आंध्रप्रदेश	74.0 फीसद
3.	तमिलनाडु	68.0 फीसद
4.	हिमाचल प्रदेश	03.0 फीसद

3. सरकारी काम कराने के लिए दिए जानेवाले घूसों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में भ्रष्टाचार घट रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
4. पिछले साल 31 फीसद लोगों को स्कूल, अदालत, बैंक या अन्य कामों के लिए 10 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की रिश्वत देनी पड़ी। 2005 में 53 फीसद लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी। यानी भ्रष्टाचार में 22 फीसद की कमी आयी है।

10 वीं कक्षा तक हिन्दी की अनिवार्यता को स्वीकृति

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने संसदीय पैनल की उस अनुशंसा को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी.बी.एस.ई. के सभी विद्यालयों तथा सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 10 तक हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

क्या है?

1. 31 मार्च को राष्ट्रपति की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया था कि 10वीं कक्षा तक हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने के लिये केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों से बात करके इस संदर्भ में एक नीति बनाए।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऐसे सभी संस्थानों, जिनके पास पृथक हिन्दी विभाग नहीं है, को ऐसे विभाग के गठन के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3. इससे पूर्व, आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत गठित पैनल ने वर्ष 2011 में राष्ट्रपति को अपनी अपनी नौवीं रिपोर्ट सौंपी थी।
4. सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इस पैनल द्वारा 117 सिफारिशों प्रस्तुत की गई थीं, जिनमें से कई सिफारिशों को सरकार ने अस्वीकृत एवं परिवर्तित भी किया है।
5. गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में हिन्दी भाषा में उत्तर लिखने एवं इंटरव्यू देने का विकल्प होना चाहिये।
6. रेलवे के लिये भाषा की आवश्यकता वाले सिर्फ वही उपकरण खरीदे जाएंगे जिनमें देवनागरी लिपि का भी विकल्प होगा।
7. रेलवे तथा एयर इंडिया के टिकिटों में सभी सूचनाएँ हिन्दी में भी होंगी ।
8. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिन्दी में उत्तर लिखने का विकल्प हो।
9. मूल सिफारिश यह थी कि "हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र (United nations) की भाषा बनाने के लिये विदेश मंत्रालय एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करे" और इसे क्रियान्वित करे। इसे संशोधित करके यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रालय इस योजना के लिये एक बजट अनुमान सुनिश्चित करे और फिर कार्यक्रम बनाने पर विचार करे।

विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र से चलेगी दिल्ली मेट्रो

मध्य प्रदेश में लगने वाले 750 मेगावाट क्षमता के विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की बिजली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) सहित तीन कंपनियों को बेची जाएगी। इसके लिए सोमवार को समझौता किया जाएगा। तीन कंपनियों के साथ बिजली बेचने का समझौता होगा।

क्या है?

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

1. मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया की बराबर हिस्सेदारी वाला संयुक्त उपक्रम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट, (आरयूएमएस) रीवा जिले की गूढ़ तहसील में स्थापित किया जा रहा है। इस उपक्रम से बनने वाली बिजली डीएमआरसी द्वारा भी खरीदी जाएगी।
2. आरयूएमएस प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली का 24 फीसद भाग डीएमआरसी को बेचा जाएगा। बाकि बिजली मध्यप्रदेश को दी जाएगी। रीवा जिले में बनने वाले 750 मेगावाट क्षमता वाले इस सौर ऊर्जा संयंत्र में 250 मेगावाट क्षमता की तीन ईकाइयां होंगी और यह संयंत्र 18 महीने में उत्पादन शुरू कर देगा।
3. विश्व का सबसे बड़ा 392 मेगावाट क्षमता का इवानपाह सौर ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के मोजावे रेगिस्तान में काम कर रहा है।

एनएससीएन का संघर्ष विराम 1 वर्ष के लिए बढ़ा

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के दो गुटों के साथ भारत सरकार ने संघर्ष विराम का करार एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने एनएससीएन के दो गुटों 'आर' और 'एनके' के साथ संघर्ष विराम की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संघर्ष विराम को बढ़ाने का यह करार इस साल 28 अप्रैल से प्रभावी होगा। संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने पर सरकार की ओर से गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सतेंद्र गर्ग और एनएससीएन 'आर' की ओर से तोशी लोंगकुमार और इम्लोंगनुक्षी तथा एनएससीएन 'एनके' की ओर से जैक जिमोमी ने हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि

1. नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) पूर्वोत्तर भारत में स्थित ईसाई आतंकी संगठन है। जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी म्यांमार और भारत के नागालैंड में आतंकी हमले करता रहता है।
2. इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नागालैंड में सभी का धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बनाना है।
3. इसमें मुख्य रूप से नगा लोगों जो पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी म्यांमार के हैं, का इस संगठन द्वारा जबर्दस्ती धर्मांतरण किया जाता है।

ईवीएम से पर्ची निकलने की व्यवस्था को हरी झंडी

अब जल्दी ही विभिन्न चुनावों में मतदान मशीन के साथ पर्ची निकलने की व्यवस्था भी बड़े स्तर पर शुरू हो सकेगी। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब तक प्रयोग के तौर पर चल रही इस व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकेगा।

क्या है?

1. 19 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने ईवीएम के साथ पर्ची निकलने की व्यवस्था के लिए धन को मंजूरी दे दी। इस वोटर वैरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) व्यवस्था में मतदान की मुख्य मशीन यानी ईवीएम के साथ ही एक प्रिंटर युक्त मशीन भी लगाई जाती है।
2. वोटर जब ईवीएम का बटन दबाता है तो उसके बाद उसकी ओर से चुने गए चुनाव चिह्न की पर्ची निकल कर सामने आती है। इसे देख कर वह आश्वस्त हो सकता है कि उसने जो बटन दबाया था, वोट उसी को गया है।
3. यह पर्ची कुछ सेकेंड के लिए दिखाई देती है, उसके बाद वह उसके नीचे बने बक्से में गिर जाती है। इस बक्से में सभी पर्चियां जमा होती रहती हैं। कोई विवाद होने पर पुराने मतपत्रों के अंदाज में इसकी गिनती की जा सकती है।
4. केंद्रीय चुनाव आयोग चाहता है कि वर्ष 2019 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर इसे लागू किया जाए। अभी तक यह सिर्फ प्रयोग के तौर पर कुछ मतदान केंद्रों पर ही उपयोग में लाया जा रहा था। एक बार धन मिल जाने के बाद इसे देश भर में लागू किया जा सकेगा।

लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में दोषी पाए गए कई नेता

विवादित ढांचा विध्वांस मामले में 19 अप्रैल को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 25 वर्षों के बाद एक बार फिर से यह मामला अति-महत्वरपूर्ण बन गया है। इस मामले में कोर्ट ने जिन 13 नेताओं पर मामला चलाने का लेकर आदेश दिया है वह नाम उस वक्त सभी की जुबान पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इन सभी

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

नेताओं पर मामला चलाने का निर्णय मामले के 25 वर्षों के बाद लिया हो लेकिन इस मामले की जांच के लिए बनाए गए लिब्राहन आयोग ने उस वक्ता करीब 68 लोगों को दोषी ठहराते हुए उनपर मामला चलाने की सिफारिश तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार से की थी।

क्या है?

1. 16 दिसंबर 1992 को इस आयोग का गठन हुआ था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल लगातार 48 बार बढ़ाया गया।
2. करीब 17 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंततः आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट तत्कानलीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी।
3. लिब्राहन आयोग की इस रिपोर्ट को 24 नवंबर 2009 को संसद में पेश किया गया था। इसमें बाबरी विध्वंस को सुनियोजित साजिश करार देते हुए आरएसएस और कुछ अन्य संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तत्का लीन मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी आयोग ने सवाल उठाए थे।
4. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 68 लोगों को दोषी ठहराया था, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, शिव सेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे, विश्व हिन्दू परिषद के नेता अशोक सिंघल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सरसंचालक के एस सुदर्शन, के एन गोविंदाचार्य, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा और प्रवीण तोगड़िया के नाम भी शामिल थे।
5. इस रिपोर्ट में तत्काालीन मुख्यमंत्री कल्यानण सिंह पर उन्हें घटना का मूकदर्शक बताते हुए आयोग ने तीखी टिप्पणी की थी। आयोग का कहना था कि कल्याण सिंह ने इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और आरएसएस को अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार दे दिए।
6. इस मामले की जांच के लिए बनाया गया एक सदस्यीय लिब्राहन आयोग देश में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला जांच आयोग है। इस पर सरकार को करीब आठ करोड़ रुपये का खर्च वहन करना पड़ा था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यूपी की सरकार को बर्खास्तख कर दिया गया था।
7. आयोग ने अगस्त 2005 में अपने आखिरी गवाह कल्याण सिंह से सुनवाई पूरी की थी। इस आयोग के समक्ष उनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और मुलायम सिंह यादव के अलावा कई नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों ने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए थे।

नए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना होगी

कंप्युटर प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थान आईसेक्ट की वार्षिक राष्ट्रीय कांफ्रेंस एवं रिन्यूवल मीटिंग कई फैसलों के साथ समाप्त हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि आईसेक्ट देश के कई अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने 1000 नए कौशल विकास केंद्र खोलेगा। इन केंद्रों पर युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

क्या है?

1. इस बैठक को संबोधित करते हुए आईसेक्ट के अमिताभ गांगुली ने कहा कि जिन राज्यों में आईसेक्ट का सघन नेटवर्क पहले से ही काम कर रहा है।
2. इन कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए और केंद्र खोले जाएंगे। आईसेक्ट का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा आईसेक्ट के माध्यम से प्रशिक्षण पाकर रोजगार प्राप्त करें।
3. पिछले तीस सालों से आईसेक्ट कौशल विकास पर आधारित शिक्षा व सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है।

अभ्यास 'वरुण'

भारत और फ्रांस की नौसेना ने युद्ध संबंधी तालमेल बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दोनों देशों की नौसेना ने 24 April 2017 को भूमध्यसागर में संयुक्त अभ्यास शुरू किया। 30 अप्रैल तक चलने वाले अभ्यास 'वरुण' में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आइएनएस मुंबई, स्टील्थ पोत आइएनएस त्रिशूल और फ्लीट टैंकर आइएनएस आदित्य हिस्सा ले रहे हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

क्या है?

1. ये जहाज विदेश में भूमध्यसागर और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर तैनात होने वाले जहाजों में शामिल होते हैं। ये जहाज सुबह फ्रांस के भूमध्यसागर तट के तुलों बंदरगाह पर पहुंचे।
2. वरुण श्रृंखला का अभ्यास वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। अब यह दोनों देशों की नौसेना के बीच संपर्क का संस्थागत रूप बन गया है।
3. मौजूदा अभ्यास समुद्री क्षेत्र में व्यवस्था कायम रखने के लिए दोस्ताना और समान सोच वाले देशों के साथ भारत की शांतिपूर्ण मौजूदगी और एकता को रेखांकित करता है।
4. संयोग की बात है कि यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल गिरीश लुथरा फ्रांस दौरे पर हैं। अभ्यास में शामिल होने वाले जहाज नौसेना के पश्चिमी कमान के हैं।

संयुक्त राष्ट्र की दो सहायक संस्थाओं के लिए चुना गया भारत

सामाजिक और आर्थिक मसलों पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की दो सहायक संस्थाओं के चुनाव को भारत ने जीत लिया है। भारत दोनों संस्थाओं में बतौर सदस्य चुना गया है। भारत के साथ 12 दूसरे देश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) की सहायक संस्था कार्यक्रम और समन्वय समिति (सीपीसी) के सदस्य निवार्चित हुए हैं। भारत को 50 में से 49 मत प्राप्त हुए। उसे एशियाई समूह में सर्वाधिक मत हासिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैय्यद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत यूएन चुनाव में फिर शीर्ष पर रहा।

क्या है?

1. ईसीओएसओसी के 50 में से 49 सदस्यों ने सीपीसी के लिए भारत के पक्ष में वोट किया।
2. सीपीसी के लिए तीन साल के लिए चुने गए 13 देशों में भारत के अलावा बर्किना फासो, ईरान, जापान, पाकिस्तान, बेलारूस, बुल्गारिया, मोलदोवा, ब्राजील, चिली, क्यूबा, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है।
3. इनका कार्यकाल जनवरी 2018 से शुरू होगा।
4. भारत के साथ 19 अन्य देश इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुने गए हैं। इसके लिए इनका चार साल का कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा।

SC ने पूछाआधार कार्ड क्यों किया अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब हमने आधार कार्ड के इस्तेमाल को वैकल्पिक करने का आदेश दिया था, फिर इसे अनिवार्य क्यों किया गया। आईटी रिटर्न फाइल करने में आधार अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वह इस बारे में फैसला सुनाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को जरूरी किया जाना चाहिए या नहीं।

क्या है?

1. एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा, 'आप आधार कार्ड को जरूरी कैसे कर सकते हैं, जबकि हमने इसे वैकल्पिक बनाने का ऑर्डर पास किया था।' इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार के पास अब इसे इस्तेमाल करने के लिए कानून है। सरकार का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने कहा, 'हमने पाया है कि तमाम मुखौटा कंपनियों में फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए पैन काड्र्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करना ही एक मात्र विकल्प है।'
2. पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करने, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने और उसमें संशोधन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। वित्त मंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार का लक्ष्य पैन काड्र्स के साथ आधार को जोड़ना है ताकि ड्यूप्लिकेट पैन काड्र्स के इस्तेमाल को रोका जा सके।
3. इससे पहले 11 अगस्त, 2015 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, 'केंद्र सरकार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

मीडिया के जरिए लोगों को बताना चाहिए कि नागरिक के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है। नागरिक को मिलने वाली किसी भी सुविधा के लिए आधार कार्ड की बाध्यता तय नहीं की जा सकती।'

ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफल

भारतीय नेवी को एक और सफलता हाथ लगी है। भारतीय नेवी ने बंगाल की खाड़ी से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एक शीर्ष नेवी अधिकारी के मुताबिक, मिसाइल परीक्षण सफल रहा। बंगाल की खाड़ी में मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।

नालंदा ने रचा इतिहास

21 अप्रैल का दिन जिले के लिए ऐतिहासिक रहा। 11वें सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों नालंदा डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम 'पीएम अवार्ड' से सम्मानित हुए। उनके साथ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी आर लक्ष्मण थे। बिहारशरीफ के हरदेव भवन में लाइव प्रसारण देख रहे अधिकारियों ने तालियां बजाकर ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया।

देश के 12 जिले में नालंदा भी

1. पीएम अवार्ड के लिए देश के 12 जिलों का चयन किया गया था। इस अवार्ड के लिए कुल 599 जिलों से ऑन लाइन आवेदन दिये गये थे। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए कुल 2345 आवेदन जिलों से भेजे गये थे।
2. पांच चरणों की जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद बेहतर कार्य के लिए देश के 12 जिलों के डीएम का चयन किया गया। इनमें अपना नालंदा भी शामिल हुआ। सूबे का इकलौता नालंदा जिला पीएम अवार्ड से सम्मानित हुआ।
3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयूजीवाई) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नालंदा डीएम को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पुरस्कार मिला है।
4. उनकी मेहनत की बदौलत ही आज जिले के हर गांव बिजली की चकाचौंध रोशनी से जगमगा रहा है। इस योजना से जिले के बिजली से वंचित 998 राजस्व गांव व उसके टोलों तक बिजली पहुंचायी गयी।
5. इनमें 44 गांव ऐसे थे यहां इससे पहले कभी भी बिजली नहीं थी। करीब एक लाख 28 हजार बीपीएल परिवारों को बिजली का कनेकशन दिया गया। छह स्थानों पर पीएसएस बनाये गये। 18 पावर ट्रांसफॉर्मरों को अपग्रेड किया गया। पुराने 11 हजार वोल्ट के वायर बदले गये। ढाई सालों में योजना पर करीब 413 करोड़ रुपये खर्च किये गये।
6. पांच साल बाद फिर नालंदा के एक और डीएम प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित हुये हैं। इससे पहले दो फरवरी 2012 को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के हाथों नालंदा के तत्कालीन डीएम विज्ञान भवन में सम्मान समारोह के दौरान चयनित 12 जिलों के विकास झलक की झलक डोक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से दिखायी गयी। करीब 10 मिनट की फिल्म में पीएम अवार्ड के लिए सलेक्ट हुए जिलों की विकास गाथा की संक्षिप्त चित्रण किया गया था।

ऑपरेशन कृष्णा

पाक के करीब 25 आतंकियों ने साधुओं की वेशभूषा में भारत-नेपाल सीमा से यूपी में प्रवेश किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने राज्य पुलिस और इंटेलीजेंस को बड़े हमले के प्रति सतर्क किया है। यूपी के सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट करते हुए संदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में 'ऑपरेशन कृष्णा' चला रही है। इसके तहत साजिश रची गई है कि 20-25 आतंकी भगवा वेशभूषा में नेपाल की सीमा से भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

क्या है?

1. आतंकियों की यह टोली बड़े मंदिरों, मेला स्थलों अथवा भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी आतंकी वारदात करेगी।
2. आतंकियों को हिंदू रीति-रिवाजों का बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। उनका मकसद धार्मिक विद्वेष फैलाना है।
3. गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आतंकी साजिश रची जा रही है।
4. खुफिया एजेंसियों के पास खबर आई थी कि योगी और पीएम मोदी पर लंदन से आतंकी हमला हो सकता है। इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

लोकपाल को पेंडिंग रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लोकपाल को पेंडिंग रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकपाल ऐक्ट के मामले में जो मौजूदा कानून है उस पर काम हो सकता है। अदालत ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि पहले बिल में बदलाव हो फिर नियुक्ति हो। लोकपाल ऐक्ट 2013 में पास हुआ और ऐसे में 3 साल से उसे पेंडिंग रखने को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मौजूदा नियम पर्याप्त है और उस पर काम हो सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की दलील थी कि लोकायुक्त की नियुक्ति वाली कमिटी में नेता प्रतिपक्ष भी होता है और इसके लिए ऐक्ट में बदलाव की दरकार है क्योंकि मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है।

क्या है?

1. सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति की मांग से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश अटर्नी जनरल ने कहा था कि मौजूदा स्थिति में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति के लिए लोकपाल कानून के तहत नेता प्रतिपक्ष जरूरी है और इसके लिए नेता की परिभाषा से संबंधित संशोधन पेंडिंग है।
3. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वर्तमान में जो स्थिति है उसमें लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि लोकपाल बिल से संबंधित तमाम संशोधन होने वाले हैं और ये तमाम प्रस्ताव संसद के सामने पेंडिंग है।
4. मौजूदा समय में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता मल्लिकार्जुन खडगे नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मांगा था लेकिन स्पीकर ने खारिज कर दिया था।
5. इस मामले में लोकपाल कानून में संशोधन के लिए संशोधन संबंधी प्रस्ताव पेंडिंग है, जिसके तहत सबसे बड़े विरोधी दल के नेता को इसमें शामिल किया जा सके। इस मामले में संसद को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए कि वह लोकपाल की नियुक्ति करे।
6. इस मामले में अधिकारों के बंटवारे का सम्मान होना चाहिए। ये संसद पर निर्भर है कि वह बिल को पास करे। वैसे लोकपाल से संबंधित करीब 20 संशोधन पेंडिंग है।
7. लोकपाल की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी और कहा गया था कि लोकपाल बिल 2013 में संसद में पास किया गया और वह 2014 से प्रभावी हो गया लेकिन सरकार लोकपाल की नियुक्ति जानबूझकर लटका रही है।
8. एनजीओ की ओर से पेश सीनियर ऐडवोकेट शांति भूषण ने कहा कि इस मामले में अदालत को दखल देना चाहिए और सबसे बड़े विरोधी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना चाहिए। गौरतलब है कि लोकपाल की नियुक्ति वाली कमिटी में पीएम, लोकसभा के स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, भारत के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के नामित जज और राष्ट्रपति द्वारा तय एक नामी हस्ती होंगे।

गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस

गंगा की निर्मल बनाने के सतत प्रयासों में आम जन को सहभागिता के लिए प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं गंगा विचार मंच के संयुक्ता तत्वाकधान में 2 मई को गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस आयोजित किया जा रहा है। देवप्रयाग समेत 11 स्थानों यथा श्रीनगर, विदुरकुटी, बिठ्ठुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हरदोई, पटना, भागलपुर, साहेबगंज, कोलकाता में एक ही दिन संकल्पम दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 30 अन्य स्थानों पर भी संकल्प दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे।

क्या है

1. केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षरण मंत्री सुश्री उमा भारती 2 मई, 2017 को विदुरकुटी, श्रीनगर एवं देवप्रयाग में आयोजित होने वाले संकल्प दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी।
2. गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस आयोजित करने का मुख्यं उद्देश्य गंगा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं उनका सक्रिय सहयोग लेना है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. इस कड़ी में स्वच्छता संदेश रैली, प्रभात फेरी, श्रमदान व स्वंच्छवता संकल्प जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक लोगों को कार्यक्रमों में सहयोजित किया जाएगा। लोगों को जागरूक बनाने हेतु अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयेाजित किए जाएंगे।
4. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से आम जन को गंगा स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागी बनाने के उददेश्य से हाल ही 16 मार्च से 31 मार्च तक गंगा स्वच्छ ता पखवाडा आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय

चीन ने अरुणाचल प्रदेश को फिर बताया अपना हिस्सा

दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से खफा चीन ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रदेश के करीब छह जगहों का नाम बदल दिया है। चीन के सिविल अफेयर्स मंत्रालय ने प्रदेश के छह जगहों के नाम बदले जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि इन्हें तिब्बत, रोमन और चीन के कैरेक्टर के साथ शुरू किया गया है।

क्या है

1. ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन जगहों के नाम वोगेंलिंग (Wo'gyainling), मिला री (Mila Ri), क्यूएडेनगार्बो री (Qoidêngarbo Ri), मेंकुआ (Mainquka), ब्यूमाला (Bümo La) और नमकापबरी (Namkapub Ri) है।
2. चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन के मुताबिक इस क्षेत्र का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) के साथ बौद्ध संबंध है। आधिकारिक चीनी मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है।
3. भारत को क्षेत्र की संप्रभुता दिखाने के लिए नाम बदले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने दक्षिण तिब्बत के 6 क्षेत्रों के नामों का मानकीकरण किया है, जो चीनी क्षेत्र का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण भारत द्वारा किया जाता है।
4. गौरतलब है कि चीन शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताकर इस पर अपना हक जमाता रहा है। भारत और चीन के बीच काफी समय से करीब 3488 किमी के क्षेत्र पर विवाद बना हुआ है।
5. यह क्षेत्र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) से लगता हुआ है। इसके अलावा अक्साई चीन के हिस्से पर भी दोनों देशों के बीच काफी समय से मतभेद है।
6. 1962 के युद्ध के बाद से ही इस क्षेत्र पर चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अब तक करीब 19 बार वार्ता हो चुकी है।
7. अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को नया नाम देने के पीछे उसकी पॉलिसी भी यही है। एक चीनी प्रोफेसर जियोंग कुंशिन के मुताबिक इस क्षेत्र को काफी लंबे समय से दक्षिण तिब्बत के नाम से जाना जाता रहा है।
8. लेकिन इसका नाम अब पहली बार बदला गया है। एक रिसर्च स्कॉलर गुओ केफान का कहना है कि यह क्षेत्र काफी समय से विवादित रहा है। भारत सरकार ने जिस विवादित क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया हुआ है चीन ने उसको कभी भी प्रमाणित नहीं किया है।

नेपाल, चीन के बीच पहला सैन्य अभ्यास शुरू

दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के प्रयास में चीन ने नेपाल के साथ 16 अप्रैल से अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। नेपाल सेना ने बताया कि दस दिवसीय सैन्य अभ्यास 'सागरमाथा फ्रेंडशिप 2017' 25 अप्रैल तक चलेगा। दोनों देश यह अभ्यास दुनिया के लिए खतरा बने आतंकवाद से मुकाबले में अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं।

क्या है

1. सागरमाथा दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी का दस्ता पहुंचा है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. चीन के अभ्यास को इस हिमालयी देश के साथ उसके सैन्य कूटनीति के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है।
3. नेपाल सेना लंबे समय से भारतीय और अमेरिकी सेना के साथ ही अभ्यास करती आ रही है। लेकिन यह पहला मौका है, जब वह चीन के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है।
4. नेपाली सेना के प्रवक्ता झंकार बहादुर ने बताया कि चीनी सैनिकों का एक छोटा दल और उतने ही नेपाली सैनिक पहली बार सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं।
5. यह अभ्यास सेना के महाराजगंज में स्थित प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ है। नेपाल ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव 24 मार्च को काठमांडू आए चीन के रक्षा मंत्री जनरल चांग वांक्यूआन के समक्ष किया था।

मशहूर वीजा प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया ने किया रद्द

ऑस्ट्रेलिया ने 18 अप्रैल को अपने उस वीजा प्रोग्राम को रद्द कर दिया, जिसका इस्तेमाल 95 हजार से ज्यादा विदेशी कामगार करते थे। इनमें से अधिकांश भारतीय हैं, जिनके बाद ब्रिटेन और चीन का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वीजा कार्यक्रम के तहत 30 सितंबर 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में 95,757 वर्कर काम कर रहे थे। अब इसकी जगह पर नई बंदिशों के साथ नया वीजा कार्यक्रम लाया जाएगा।

क्या है

1. रद्द किए गए वीजा प्रोग्राम का नाम है- 457 वीजा। इसके जरिए कंपनियों को स्किल्ड जॉब्स में विदेशी कामगारों को अधिकतम चार साल तक रखने की इजाजत मिलती है।
2. यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई कामगारों की कमी मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल ने कहा, हम प्रवासियों का देश हैं, लेकिन यह भी सच है कि ऑस्ट्रेलियाँ में नौकरियों के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वरीयता मिलनी चाहिए। इस वजह से हम अस्थाई तौर पर विदेशी कामगारों को हमारे यहां आने की इजाजत देने वाले 457 वीजा को खत्म कर रहे हैं।
3. हम 457 वीजा को अब उन नौकरियों तक पहुंचने का जरिया नहीं बनने देंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को मिलनी चाहिए। पीएम ने कहा कि स्किल्ड जॉब्स के क्षेत्र में वह 'ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट' की नई नीति अपनाने जा रहे हैं।
4. ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि नए वीजा कार्यक्रम के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में अहम स्किल्स की कमी को भरने के लिए ही विदेशी कामगारों को लाया जाए।
5. टर्नबुल का यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है, जब हाल ही में वह भारत दौरे से लौटे हैं। यहां उन्होंने सिक्यॉरिटी, आतंकवाद, शिक्षा, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। इसके अलावा, छह समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे।

प्रथम 'भारत इंडोनेशिया ऊर्जा फोरम'

केन्द्रीय विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पियूष गोयल और इंडोनेशिया गणराज्य के ऊर्जा और खनिज संसांधन मंत्री महा महीम श्री इग्नासियस जोनान ने 20 अप्रैल, 2017 को जकार्ता में प्रथम 'भारत इंडोनेशिया ऊर्जा फोरम' में भाग लिया। ऊर्जा फोरम से पहले तेल और गैस संबंधी दूसरे संयुक्त कार्यदल, कोयला संबंधी चौथे संयुक्त कार्यदल और नई और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रथम संयुक्त कार्यदल की बैठकें आयोजित की गई। ऊर्जा फोरम के दौरान तीनों संयुक्त कार्यदलों की रिपोर्ट दोनों मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

क्या है

1. तेल और गैस संबंधी दूसरे संयुक्त कार्यदल की बैठक में भारत और इंडोनेशिया के नीति फ्रेमवर्क और दोनों देशों में तेल और गैस क्षेत्र में क्षमता निर्माण और व्यापार के अवसर बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
2. कोयला संबंधी चौथे संयुक्त कार्यदल की बैठक के चार सत्र आयोजित किए गए। प्रमुख भारतीय कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि भी इन बैठकों में मौजूद थे। इनमें नीति गत फ्रेमवर्क और क्षमता निर्माण के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. नई और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रथम संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक का आयोजन वीडियो-कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। दोनों देशों ने एक-दूसरे के यहां निवेश के अवसरों पर विचार किया।
4. भारत सरकार के पैट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इंडोनेशिया के ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के बीच तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत आपसी लाभ के लिए एक सहकारी संस्थागत फ्रेमवर्क कायम करने का प्रावधान है।
5. भारत इंडोनेशिया से कोयला आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। 2016 में भारत ने इंडोनेशिया से 3.5 अरब अमरीकी डालर मूल्य का कोयला आयात किया। कई भारतीय कंपनियों ने इंडोनेशिया में कोयला खदानों में निवेश किया है।
6. 2015-16 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15.90 अरब अमरीकी डालर मूल्य का था, जिसमें इंडोनेशिया का निर्यात 13.06 अरब अमरीकी डालर मूल्य का था जबकि भारत का निर्यात 2.84 अरब अमरीकी डालर मूल्य का था। दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि व्यापार संतुलन कायम करने के लिए भारत से इंडोनेशिया का निर्यात बढ़ाया जायेगा।

भारत और रूस के बीच होगा पहला त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास

पिछले साल पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कर के अपने 'करीबी दोस्त' भारत को नाराज करने वाला रूस अब भारत के साथ त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास करने वाला है। भारत और रूस के बीच इस साल के अंत में एक बड़ा सैन्य अभ्यास होगा जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की भागीदारी के साथ त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास होने की भी संभावना है। मजबूत सामरिक रिश्ते रखने वाले भारत और रूस के बीच इस तरह का यह पहला युद्ध अभ्यास होगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी और नेवी रूस के साथ अलग से सैन्य अभ्यास श्इंद्रश करेंगी।

क्या है

1. अक्टूबर नवंबर में रूस में होने सैन्य अभ्यास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी तीनों सेनाओं के जवान और हथियार शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब भारत की तीनों सेनाएं एक साथ किसी देश का साथ अभ्यास करेंगी।
2. रूस भारत के लिए पिछले काफी दशकों से सबसे बड़ा रक्षा सप्लायर रहा रहा है। 1960 के दशक से देखा जाए तो भारत रूस से 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियार और सैन्य सामग्री खरीद चुका है, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच उस अनुपात में सैन्य अभ्यास नहीं होता।
3. भारतीय वायु सेना ने 2014 में रूसी वायु सेना के साथ एक अभ्यास 'एविया इंद्र' में भाग लिया था। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच लगभग हर साल सैन्य अभ्यास होते हैं। इन सैन्य अभ्यासों में मालाबार अभ्यास भी शामिल है जिसमें जापान भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा काउंटर टेरर अभ्यास वज्र प्रहार भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच होता रहा है।
4. भारत और रूस ने इंद्र अभ्यास के लिए शुरुआती तैयारी को लेकर बैठक हो चुकी है। इसके फॉर्मैट, इसमें शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या और हथियारों को लेकर बातचीत हुई है। इसे अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही दो और कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी।

चार दिन में सूख गई स्लिम्स नदी

कनाडा से बहने वाली 150 मीटर चौड़ी स्लिम्स नदी सिर्फ चार दिन में सूख गई। ऐसा मौसम में बदलाव की वजह से ग्लैशियर पिघलने के चलते हुए। कास्कावुल्श ग्लैशियर से निकलने वाली स्लिम्स नदी सैकड़ों से सालों से बह रही थी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम में आए बदलाव की वजह से ग्लैशियर की बर्फ काफी तेजी से पिघली जिससे नदी के पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि श्गायबश ही हो गया।

क्या है

1. दरअसल तेज बहाव कि वजह से एक अलग रास्ता बन गया था। बहाव की दिशा बदलने की वजह से नदी अपनी पुरानी जगह से लगभग खाली हो गई। खबर के मुताबिक, अब यह नदी अलास्का की खाड़ी की तरफ बहती है। वैज्ञानिक कुदरत के इस कमाल को श्रिवर पाइरेसीश (नदी की चोरी) का नाम दे रहे हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. रिपोर्ट में एक भूविज्ञानी ने बताया कि उन्होंने नदी वाली जगह का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि नदी लगभग सूख चुकी है।
3. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के बड़े बदलाव में काफी लंबा वक्त लगता है। उनका कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से स्लिम्स नदी पतली धारा में बदल गई, जबकि दूसरी तरफ ग्लैशियर के पानी की दिशा बदलने से अलास्का नदी कई गुना बड़ी हो गई है। इससे पहले ये दोनों नदियां एक जैसी थीं।

चीन ने भेजा पहला मालवाहक अंतरिक्ष यान

महत्वाकांक्षी चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए चीन ने अपना पहला मानव रहित कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, तिआंग्जू। को दक्षिणी हेईनान प्रांत के वेनचांग स्पेस स्पेस लाउंच सेंटर से रवाना किया गया।

क्या है

1. तिआंग्जू-1 को वेनचांग के हेईनान प्रांत के प्रायद्वीप से भेजा गया। विमान के अंतरिक्ष में रवाना करने के कुछ ही मिनट बाद बीजिंग ने इसे सफल मिशन करार दिया।
2. मानव रहित कार्गो स्पेसक्राफ्ट के तिआनगोंग 2 स्पेस सेंटर में पहुंचने के बाद वहां पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। इससे पहले चीन की तरफ से तिआनगोंग 2 को पिछले साल सितंबर में भेजा गया था। जबकि, अगले साल 20 टन का स्टेशन का कोर मॉड्यूल अगले साल भेजा जाएगा।
3. चीन इस समय साल 2022 तक अंतरिक्ष में अपना स्थायी स्टेशन बनाने की प्रक्रिया में है। इस कोशिश में वह अंतरिक्ष यान और राकेट का फरवरी से कई परीक्षण कर चुका है।
4. तियांझू-1 चीन की ओर से विकसित पहला मालवाहक अंतरिक्ष यान है। यह परिक्रमा कर रहे प्रायोगिक स्पेस स्टेशन तियांझू-2 पर उतरेगा और ईधन की आपूर्ति करेगा। यह अंतरिक्ष यान धरती पर वापस आने से पहले कई परीक्षणों को भी अंजाम देगा।

यूरोप के प्रदूषण से ही भारत में पड़ा भयानक सूखा

लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने में भारत में पड़े सूखे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वर्ष 2000 में भारत में सूखे के लिए यूरोप जिम्मेदार था। यूरोप के वायु प्रदूषण के कारण भारत में सूखा पड़ा था जिसमें करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ताओं की एक स्टडी में यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने साल 2000 में भारत में हुई बारिश पर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रभाव की गणना की है। उन्होंने पाया कि उत्तरी गोलार्ध मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के उत्सर्जन के कारण भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में 40 फीसद तक बारिश कम हुई थी। यूरोप के उत्सर्जन के कारण दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में भी 10 फीसद बारिश में कमी आई थी।

क्या है

1. शोधकर्ताओं का कहना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य तौर पर कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से होता है। इससे अमलीय बारिश, हृदय और फेफड़ों के रोग, पोधों के विकास का रुकना जैसे कई भयानक प्रभाव पड़ते हैं।
2. सल्फर के कारण वातावरण में ठंड का प्रभाव बढ़ जाता है चूंकि इसके छोटे-छोटे कण और पानी की बूंदें सूरज की किरणों को रोक देते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उत्सर्जन के कारण दक्षिण में भी गर्मी पर असर पड़ सकता है और का समय बदल सकता है जिसके परिणाम और भी खराब होंगे।
3. आईसीएल के ग्रैंथम संस्थान के अपोस्टोलोस वाउलागार्की का कहना है कि स्टडी हमें बताती है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में हुए उत्सर्जन का दूसरे पर गहरा असर पड़ता है। एशिया के नजदीक होने के कारण इस पर प्रभाव अधिक है लेकिन इसका असर यूरोप और अमेरिका तक भी है।

एजी600 की खासियत

1. विमान की लंबाई 37 मीटर, पंख 38.8 मीटर लंबे
2. अधिकतम 53.5 टन भार के साथ उड़ने में सक्षम
3. महज 20 सेकेंड में 12 टन पानी भरने की क्षमता
4. एक बार में 370 टन पानी ले जाने में सक्षम

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. मौसम का एक डिग्री सेल्सियस गर्म या ठंडा होना तो सामान्य सी बात है। लेकिन जब बात पूरी धरती के औसत तापमान की हो तो इसमें मामूली सी बढ़ोतरी के भयंकर नतीजे सामने आते हैं।
5. नासा के मुताबिक धरती का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब भी संभल जाएं! धरती एक डिग्री गर्म हुई तो पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे।

चीन की पहले एंफीबियस ने भरी पहली उड़ान

चीन के पहले एंफीबियस (जमीन-पानी में उतरने में सक्षम) विमान ने पहली सफल उड़ान भरी। जल्द ही इसको समुद्र में उतारने की तैयारी है। बीजिंग का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एंफीबियस विमान है। बोइंग 737 के आकार वाले एजी600 नामक विमान का उड़ान परीक्षण शनिवार को दक्षिणी चीन के झुहाई शहर में किया गया। पिछले जुलाई से ही कई स्तरों पर विमान का परीक्षण चल रहा था। फरवरी में परीक्षणों में विमान के सभी चारों इंजन खरे उतरे पाए गए।

क्या है

1. इस विमान का उपयोग मुख्य रूप से आपात स्थितियों में राहत-बचाव कार्यो, जंगलों में आग पर काबू पाने और समुद्री पर्यावरण की निगरानी में किया जाएगा।
2. विमान को तैयार करने में करीब आठ साल का वक्त लगा। इसमें 90 फीसद से अधिक स्वदेशी पुर्जो का इस्तेमाल किया गया है। इस विमान के लिए अब तक 17 आर्डर भी मिल चुके हैं।

आर्थिक

पंचवर्षीय योजना का अंत

देश में तेजी से बदलाव लाने के लिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक 23 अप्रैल 2017 को हुई। सूत्रों के मुताबिक, नीति (नैशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग की बैठक में भारत में बदलाव लाने का अगले 15 साल का रोडमैप पेश हुआ। इससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनी करती थीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को खत्म होनेवाली थी, लेकिन मंत्रालयों को अपने कामकाज निपटाने के लिए आखिरी पंचवर्षीय योजना को छह महीने का विस्तार दे दिया गया है। इसकी अवधि पूरे होते ही साथ ही नेहरू के समाजवाद के इस प्रमुख घटक का खात्मा हो जाएगा। नई व्यवस्था में तीन साल का ऐक्शन प्लान बनेगा जो सात वर्षीय स्ट्रैटिजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्युमेंट का हिस्सा होगा। योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग 1 अप्रैल को तीन वर्षीय ऐक्शन प्लान लॉन्च चुका है।

योजना आयोग से कैसे अलग है नीति आयोग?

1. योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग नीतिगत दिशानिर्देश तय करेगा। इसका मूल सिद्धांत 'सहकारी संघवाद' है। सबसे अहम अंतर यह है कि नीति आयोग के पास फंड ग्रांट करने की शक्ति नहीं है। वह राज्यों की ओर से कोई फैसला नहीं ले सकता। यह सिर्फ सलाहकार संस्था के रूप में काम करता है।
2. त्रिवर्षीय कार्य योजना में किसी स्कीम या अलोकेशन का जिक्र नहीं होता है क्योंकि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय अधिकार है ही नहीं। चूंकि इसे केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल सकती, इसलिए इसके सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
3. सरकार ने योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के रूप में खर्चों के श्रेणीकरण खत्म कर दी, इसलिए नीति आयोग के दस्तावेजों की वित्तीय भूमिका नहीं होती है। वो सरकारों के लिए सिर्फ नीति निर्धारण को लेकर निर्देश देने तक सीमित हैं।

क्या थी पंचवर्षीय योजना?

1. पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार का आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम शामिल होता था। तत्कालीन यूएसएसआर के प्रेजिडेंट जोसफ स्टॉलिन ने पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत साल 1920 में की थी।
2. 1947 में मिलने के बाद भारत ने भी समाजवाद का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों की मौजूदगी की वजह से यहां यूएसएसआर की तरह व्यापक योजना लागू करना मुश्किल था।
3. इसलिए, यहां सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं। साल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में आई। इसके पीछे का मकसद सरकारी धन को समानुपाती विकास पर खर्च करने का था।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. क्या मिला?
5. पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के सामाजिक क्षेत्र का स्तर उठाने और भारी उद्योग के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम में यह सुनिश्चित होता था कि पैसे सबसे जरूरी जगह पर खर्च हों।

अब क्यों नहीं रही जरूरत?

1. भारत जैसे विविधपूर्ण और बड़े देश में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एक खास सीमा से आगे कारगर नहीं हो सकती। चूंकि, योजना आयोग केंद्र सरकार के तहत आ रहा था, इसलिए धन आवंटित करते वक्त इसका इस्तेमाल कई बार विरोधी राज्यों को दंडित करने में भी होता रहा।
2. इसमें टॉप-टु-बॉटम अप्रोच की वजह से महसूस किया जाने लगा कि राज्यों को अपने खर्च की प्लानिंग करने में ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। योजना आयोग ने कई बार राज्यों पर दादागिरी दिखाई जबकि राज्यों को अपने खर्चों की ज्यादा अच्छी समझ होती है।

'द बेटर बिजनेस बेटर वर्ल्ड' रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, मात्र एक फीसदी भारतीयों के पास ही देश की 53 फीसदी संपत्ति है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि आर्थिकतौर पर देश में कितनी असमानता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि असमानता, गरीबी को दूर करने के लिए भारत को एक दूसरे तरह के आर्थिक मॉडल की जरूरत है। यह भी कहा गया कि दूसरे देशों की तरह भारत में विकास राज्यों से बाहर नहीं निकल पा रहा है।

क्या है

1. रिपोर्ट 'द बेटर बिजनेस बेटर वर्ल्ड' में कहा गया है कि आर्थिक विषमता में भारत रूस के बाद दूसरे स्थान पर है जहां सिर्फ एक फीसदी लोगों के पास देश की 53 फीसदी संपत्ति है।
2. यूएनजीसी के सीईओ लाइज किंगो के अनुसार, सतत विकास लक्ष्य के तहत भारत में करीब एक ट्रिलियन डॉलर तक प्राइवेट सेक्टर से निवेश मिल सकता है। जाकि दुनिया में यह निवेश कुछ 12 ट्रिलियन डॉलर है। यह निवेश -कृषि, खाद्यान्य, ऊर्जा, शहर और स्वास्थ्य में हो सकता है।
3. इस निवेश से भारत में 2030 तक 72 मिलियन नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ जीएसटी बिल

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक 2017 विधानसभा में पारित हो गया। कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया। लेकिन अमित जोगी ने इसका विरोध किया। बिल पास होने पर सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी देश को एकसूत्र में पिरोकर विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। इसके बाद सुकमा हमले को लेकर विधानसभा में चर्चा होनी है। हमले से कांग्रेस इसे लगातार सरकार की नाकामी बता जिम्मेदारों को इस्तीफा देने की बात कह रही है। ऐसे में विधानसभा की विशेष बैठक में भी विपक्ष का लक्ष्य सरकार को सुकमा हमले पर घेरना रहेगा।

चौथा राष्ट्रीय मानक सम्मेलन

वाणिज्य विभाग, भारत सरकार 1-2 मई, 2017 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) और अन्य भागीदारों के सहयोग से चौथा राष्ट्रीय मानक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार के बदले परिदृश्य में जागरूकता लाने और 'मानक' के बढ़ते महत्व पर उद्योग, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नियामक/मानकों और अनुरूप मूल्यांकन निकायों को तैयार करना है।

क्या है

1. मानक सम्मेलन टैरिफ के घटते महत्व और माल व सेवा व्यापार दोनों में मानक और नियमन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है।
2. इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि विभेदक मानकों के दिन-घरेलू बाजार के लिए कम और निर्यात के लिए उच्च- खत्म हो चुके हैं और अगर ऐसी स्थित में भारतीय उद्योग को सुरक्षित और उभरना है, तो उसे वैश्विक मानकों को अपनाने की आवश्कता है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. मंत्रालयों/नियामकों/राज्य सरकारों को भी यह महसूस करना होगा कि यदि उन्हें अपने उद्देश्यों में सफल होना है तो उन्हें अपनी तमाम योजनाएं वैश्विक स्तर पर निर्मित करनी होगी।
4. एक अच्छी मानक व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री के विजन 'मेक इन इंडिया' अभियान को पूरा करेगी। यह हमारे घरेलू उद्योग और उपभोक्ताओं की कीमत पर घरेलू बाजार में असुरक्षित/उप-मानक वाले आयात की बाढ़ को रोकने में भी मदद करेगा।

लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरण जेटली को सौंपी। अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था। वेतन समिति ने अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़न दस्ता, बालों की कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनिफार्म, सतर्कता और धुलाई जैसे भत्तों को समाप्त करने या उन्हें समाहित करने का सुक्षव दिया था। जेटली को रिपोर्ट सौंपने के बाद लवासा ने कहा कि समिति ने विभिन्न अंशधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है।

क्या है

1. अब इस रिपोर्ट की समीक्षा सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति करेगी और उसके बाद इसके मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। समिति ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुक्षाव दिया है। समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि का सुक्षाव दिया है।
2. यदि वेतन आयोग की भत्तों पर सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता है तो एक अनुमान के अनुसार इससे सरकार पर 29,300 करोड़ रुपये का बोक्ष पड़ेगा। लवासा ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को संशोधित भत्तों के भुगतान की तारीख पर अंतिम फैसला करेगी।
3. बता दें कि सातवें वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है।
4. नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई।
5. अब जब अशोक लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला सरकार की ओर से ले लेंगे।
6. वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को आरंभ में 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी तय किया था और कहा गया था कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी क्रमशः हो जाएगा।
7. इतना ही नहीं वेतन आयोग (पे कमिशन) ने यह भी कहा था कि जब डीए 100 फीसदी हो जाएगा तब यह दर 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी क्रमश : एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए हो जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि वह इस दर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

15 साल का विजन

सरकारी शोध संस्थान ने 15 साल के अपने विजन में ऐसे नए भारत का सपना बुना है जिसमें देश के सभी नागरिकों के पास शौचालय की सुविधा, दुपहिया या कार, एसी और डिजिटल कनेक्टिविटी हो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने संचालन परिषद की बैठक में 2031-32 के लिए विजन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। 'भारत 2030-31: दृष्टिकोण, रणनीति और कार्ययोजना अजेंडा' में एक ऐसे भारत का सपना देखा गया है जिसमें पूरी तरह शिक्षित समाज हो और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुंच उपलब्ध हो। इसके साथ ही इस विजन यानी दृष्टिपत्र में सड़कों, हवाई अड्डों और जलमार्गों के बड़े और आधुनिक नेटवर्क की बात की गई है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

क्या है

1. इसमें ऐसे स्वच्छ भारत की कल्पना है जिसमें हर नागरिक को अच्छी हवा और स्वच्छ पानी सुनिश्चित हो।
2. इसका मानना है कि प्रति व्यक्ति आय 2031-32 में बढ़कर तीन गुना यानी 3.14 लाख रुपये हो जाएगी जो कि 2015-16 में 1.06 लाख रुपये थी। इसमें कहा गया है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) यानी अर्थव्यवस्था 469 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी। वर्ष 2015-16 में यह 137 लाख करोड़ रुपये रही।
3. विजन के मुताबिक केंद्र और राज्य का कुल खर्च 2031-32 तक 92 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 130 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा जो कि 2015-16 में 38 लाख करोड़ रुपये था।
4. पंद्रहवर्षीय विजन और सात वर्षीय कार्य योजना दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी तरह रविवार को परिषद के सदस्यों को तीन वर्षीय एक्शन अजेंडा भी बांटा गया। इसे भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
5. विजन प्रेजेंटेशन के मुताबिक 2031-32 तक प्रधानमंत्री के वाइब्रेंट इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
6. प्रेजेंटेशन में कहा गया, श्हमें भारत को एक समृद्ध, स्वस्थ, सुरक्षित, भ्रष्टाचार-मुक्त, ईंधन की प्रचूरता वाले, पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली देश में बदलना चाहिए।'

सिल्क रोड परियोजना में भारत की भागीदारी अहम

चीन की महत्वाकांक्षी सिल्क रोड परियोजना के लिए भारत की भागीदारी काफी अहम है। नई दिल्ली के रुख का असर उन कुछ देशों के फैसले पर पड़ेगा, जो अरबों डॉलर की इस परियोजना में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं। यह बात चीन के सरकारी अखबार ने कही।

क्या है

1. ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख के अनुसार, भारत की भागीदारी काफी अहम है। यह न सिर्फ भारत की आबादी, श्रम संसाधन और बाजार बल्कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में उसके राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से भी अहम है।
2. भारत के रुख का इस क्षेत्र के देशों के फैसले पर असर पड़ेगा। चीन महत्वाकांक्षी 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना पर अगले महीने वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।
3. इसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रधानमंत्री समेत 28 देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरिडोर (सीपेक) प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) का ही हिस्सा है।
4. गुलाम कश्मीर से गुजरने के कारण भारत शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है। भारत ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की अभी तक घोषणा नहीं की है।

जेनरिक दवा नहीं लिखी तो रद हो सकता है डॉक्टर का लाइसेंस

देशभर के डॉक्टरों को लाइसेंस जारी करने और उनके कामकाज पर नजर रखने वाली भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआइ) ने अब डॉक्टरों के लिए दवाओं का जेनरिक नाम ही लिखना अनिवार्य कर दिया है। अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई में परिषद को संबंधित डॉक्टर का लाइसेंस तक रद करने का अधिकार है।

क्या है

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद कानून के तहत रजिस्टर्ड सभी डॉक्टरों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित प्रावधान का बिना किसी लापरवाही के पालन करें। उन्होंने यह बात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद कानून के संशोधित प्रावधान 1.5 के संबंध में कही है।
2. एमसीआइ ने पिछले साल सितंबर में ही अधिसूचना जारी कर इस प्रावधान में संशोधन किया था। इसमें डॉक्टरों को जेनरिक दवा ही लिखने को कहा था।
3. ताजा आदेश में उन्होंने साफ कहा है कि सभी फिजीशियन को जेनरिक नाम और स्पष्ट अक्षर से ही दवा लिखनी चाहिए और जहां तक संभव हो बड़े अक्षरों का उपयोग करें।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा जरूरत के अनुरूप ही लिखी गई हो। परिषद ने सभी राज्य सरकारों, राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को भी इस निर्देश का पालन करवाने को कहा है।
5. इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वह चाहते हैं कि लोगों को महंगी दवा लेने के लिए मजबूर न होना पड़े और इसके लिए सरकार जल्द ही नियम बनाएगी। इसके बाद औषधि विभाग भी संबंधित नियम तैयार कर रहा है।

विज्ञान और तकनिकी

एचआईवी जैसे वायरस का 1.1 करोड़ साल पहले खात्मा

एचआइवी प्रकार के एक प्राचीन वायरस का पता चला है। नए शोध का दावा है कि हमारे आदिम पूर्वजों ने संभवत: 1.1 करोड़ साल पहले इस वायरस का खात्मा कर दिया था। इसके जीवाश्म डीएनए का यह पता लगाने के लिए परीक्षण किया गया कि ये प्राचीन वायरस कब चरम पर थे।

क्या है

1. अमेरिका की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारे आदिम पूर्वजों ने वायरस से बचाव का तंत्र विकसित कर लिया था।
2. शोधकर्ता पॉल बेनिएज ने बताया कि वायरस जीवाश्मों के विश्लेषण से प्राचीन काल में हुई घटनाओं पर नई रोशनी पड़ सकती है। यह शोध तो महज एक नमूना है जिससे यह जाहिर होता है कि वायरस खुद को कैसे जेनेटिक मैटेरियल मुहैया करा सकते हैं।
3. रेट्रोवायरस प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मौजूद है और कोशिकाओं को संक्रमित करने के बाद इनका अस्तित्व स्थायी हो सकता है। रेट्रोवायरस एचआइवी समेत वायरसों का एक वर्ग है।
4. शोधकर्ताओं ने रेट्रोवायरस जीवाश्म का विश्लेषण किया। इससे पता चला कि इस वायरस को 1.1 करोड़ साल पहले जड़ से खत्म कर दिया गया था।

ग्लेशियर की आकृति से चलेगा खतरे का पता

वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पर मंडराते खतरे और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के बारे में पता लगाने का नया तरीका खोज निकाला है। उनका कहना है कि ग्लेशियर की आकृति का विश्लेषण कर इसके सिमटने के खतरे के बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है।

क्या है

1. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी ग्रीनलैंड ग्लेशियर के आकार को लेकर अध्ययन किया। ग्रीनलैंड ग्लेशियर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मगर वातावरण में बढ़ती गर्मी के कारण पिछले कई दशक से इसका आकार सिमट रहा है।
2. हालांकि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में होने वाले बदलाव का आकलन कर पाना जटिल प्रक्रिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नई तकनीक की मदद से यह पता लगाना आसान होगा कि आने वाली सदी में ग्रीनलैंड के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी होगी।
3. शोधकर्ता डेनिस फेलिकसन ने कहा कि ग्लेशियर के कारण समुद्र के जल स्तर में होने वाला बदलाव एक इंच से कुछ फुट तक का भी हो सकता है। हमने इस अंतर को समझने का प्रयास किया है।

ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत योजना

भारत जल्द ही एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्घाटन करेगा, जिसका उद्देश्य 2030 देश के अधिकतर वाहनों को बैटरी चालित वाहनों में बदलना होगा। इस साहसिक कार्य के लिए उद्यमी एलन मस्क एक उचित कदम उठाएंगे और एक बैटरी लीजिंग रणनीति तैयार करेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार इस योजना की शुरुआत आने वाले कुछ महीनों

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

में कर दी जाएगी, इसके लिए निर्माताओं को सीमित कर में छूट और वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उन्हें बिना बैटरी के ही बेचा जाएगा।

क्या है

1. यह रणनीति अमेरिका, जापान और चीन सहित कई देशों के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिन्होंने बिजली के वाहनों के लिए सब्सिडी में अरबों डॉलर का प्रावधान किया हुआ है।
2. इन देशों ने भारत को ऐसा न करने की सलाह दी है, हालांकि, भारत, इसके विपरीत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है जो कि पहले चरण में सार्वजनिक परिवहन के साथ शुरू होगा।
3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे।
4. भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा बनाई गई दुपहिया और तिपहिया वाहन और गैर-वातानुकूलित शहरी बसें, योजना के हिस्से के रूप में बैटरी के बिना ही बेची जाएंगी, इस प्रकार इसकी कीमतों में 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।
5. इन वाहनों में लगने वाली बैटरी को निर्धारित कीमतों पर किराये पर लिया जा सकेगा और उन्हें आप रिचार्ज करवा सकेंगे। इसके बाद निजी वाहनों पर काम किया जाएगा।
6. सूत्रों के अनुसार इस बैटरी को बदलने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। अभी तैयार किए गये मॉडल एसी कार और एसी बस में काम नही करेंगे।

ब्रह्मांड में एक और 'पृथ्वी' मिली

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक और 'पथ्वी' खोज निकाली है। पृथ्वी से मिलते जुलता 'एलएचएस1140बी' ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर है। यह पृथ्वी की ही तरह पथरीला है, इसका मौसम न ज्यादा गरम और न ज्यादा ठंडा है। साथ ही इसका तापमान पानी की मौजूदगी के लिए सटीक है, जिस कारण इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं अब तक मिले ग्रहों में सबसे अधिक है। यह शोज जर्नल नेचर में छपी है।

क्या है

1. इन ग्रहों में जीवन की खोज करने की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि है, अब ऐसा समय आ गया है जब हमें आने वाले समय में और अधिक शक्तिशाली दूरबीन बनानी होगी। ताकि इस तरह के अध्ययन में सुविधा हो सके।
2. पिछले एक साल के अंतराल में सौर मंडल के बाहर करीब पांच ऐसे ग्रह खोजे गए हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है।
3. एलएचएस1140बी इन सब में पृथ्वी से सबसे अधिक मेल खाता है। यहां का वातावरण, इसकी सतह और इसका तारा इस ग्रह को रहने योग्य बनाता है।

अब कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार होगी शुद्ध हवा

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की शुद्ध हवा ग्लोबल वॉर्मिंग और वायु प्रदूषण से लड़ने की दिशा में अमेरिकी वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को जैविक पदार्थ में बदलने में सफलता हासिल की है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थ और शुद्ध हवा उन्मुक्त होते हैं। इस जैविक पदार्थ का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जा सकता है।

पर्यावरण को फायदा

1. संश्लेषण के लिए वैज्ञानिक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं।
2. मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क आयन का समूह है, जिससे

प्रकाश संश्लेषण

1. इसके जरिए पेड़-पौधे सूर्य की रौशनी का इस्तेमाल कर अपना भोजन तैयार करते हैं।
2. इस प्रक्रिया के लिए वह ईधन के तौर पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं।
3. प्रक्रिया के दौरान वे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वैज्ञानिकों के इस प्रयोग में अंतर सिर्फ इतना है कि यहां भोजन की जगह जैविक पदार्थ बनते हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

रसायनिक प्रक्रिया शुरू की जाती है।

3. प्रक्रिया के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जैविक पदार्थ में तोड़ दिया जाता है।
4. रासायनिक प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को फारमेट और फॉर्माइड्स में तब्दील कर देती है। सूर्य की रोशनी के अभाव में इनका इस्तेमाल कर बिजली पैदा की जा सकती है।
5. इसी के साथ ऑक्सीजन अवमुक्त होती है।

ग्लोबल वॉर्मिंग की काट

1. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है।
2. इन गैसों के चलते सूर्य की इंफ्रा रेड किरणें धरती पर आ तो जाती हैं पर निकल नहीं पाती। इससे धरती का औसत तापमान बढ़ता है, जिससे गर्मी बढ़ती है। इसी को ग्लोबल वॉर्मिंग कहते हैं। इसी के चलते धरती का मौसम चक्र गड़बड़ा रहा है। तमाम प्रतिकूल प्रभाव दिख रहे हैं।

साल 2015 में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

1. 82 फीसद कार्बन डाईऑक्साइड
2. 10 फीसद मीथेन
3. 5 फीसद नाइट्रस ऑक्साइड
4. 3 फीसद फोरिनेटेड गैसें

मिल गई भूलने की दवा

वैज्ञानिकों ने भूलने बीमारी की दवा खोज ली है। यह दवा दिमाग से संबंधित बीमारियों समेत भूलने की दिक्कत को दूर करने में वरदान साबित होगी। वैज्ञानिकों ने जिन दो नई दवाओं की खोज की वह इंसान के दिमाग से संबंधित समस्याओं के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दवा इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगी क्योंकि पहले से ही कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल के टॉक्सीकोलॉजी विभाग की एक शोधकर्ता ने इस कामयाबी पर मीडिया से खुशी जाहिर की है।

क्या है

1. इस नई दवा का प्रयोग चूहों में किया गया जो सफल रहा। अगले दो-तीन सालों इसका प्रयोग इंसानों में किए जाने की संभावना जताई गई है।
2. दिमाग की कोशिकाओं में जब कोई वायरस पहुंचता है तो वह कोशिका में बनने वाले प्रोटीन को नियंत्रित करने लगता है। ऐसा होने कोशिका प्रोटीन का निर्माण बंद कर देती है और कुछ समय बाद खुद को समाप्त कर लेती है।
3. ऐसी कोशिका को फिर से जीवत करने का कोई उपाय नहीं था और इसी वजह से ब्रेन हैम्ब्रेज या अल्जाइमर जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। लेकिन नई दवा वायरस से प्रभावित कोशिका को प्रोटीन संश्लेषित करने में मदद करती है। इस दवा से किसी नई दिमाग की नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है।
4. इससे पहले 2013 में भी ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने दावा किया था कि उसने जानवरों में दिमाग की कोशिकाओं से मृत होने से रोक दिया था। उनका यह दुनियाभर की मीडिया सुर्खियां बना था। लेकिन बाद में कहा गया इस दवा का इस्तेमाल इंसानों में संभव नहीं है क्योंकि इसके इस्तेमाल से कि अंग के खराब होने की आशंका है।
5. इस नई दवा की खोज के बारे में अल्जाइमर सोसाइटी के डॉ डाउग ब्राउन का कहना है कि वह इस पूरे शोध और प्रयोग से काफी उत्साहित हैं।
6. इन नई दो दवाओं में से एक पहले से ही डिप्रेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। वहीं एक दूसरे विशेषज्ञ ने कहा कि यह बहुत ही जरूरी और चौंका देने वाला शोध है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

शुक्र मिशन के लिए इसरो ने मांगे वैज्ञानिकों के सुझाव

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्र ग्रह पर भारतीय मिशन की घोषणा करते हुए वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए आमंत्रित किया है और सुझाव भी मांगे हैं। इन सुझावों में वैज्ञानिकों से पूछा गया है कि शुक्र के किन-किन पहलुओं का अध्ययन किया जाए। इसरो के अनुसार, शुक्र की मिशन पर जाने वाले 500 वाट पावर से लैस सैटेलाइट का वजन 175 किग्रा है। शुक्र के चारों ओर का प्रस्तावित कक्ष लगभग 500 ◦ 60,000 किलोमीटर होगी जो कई महीनों में सिमटेगी और ग्रह की कक्षा के करीब आ जाएगी।

क्या है

1. मिशन का फोकस वहां के वातावरण और सतह के अध्ययनों, सूर्य के साथ शुक्र के संबंधों, जैविक प्रयोगों और तकनीकी सबूतों पर होगा।
2. इसरो के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अभी इस मिशन के लांच की तारीख नहीं तय हुई है। इस मिशन का महत्व बताते हुए इसरो ने कहा कि वीनस को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना में पृथ्वी के ही समान है। यह माना जाता है कि दोनों ग्रहों की संरचना एक समय में 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी।
3. इसरो के अनुसार, 1960 की शुरुआत में में सोवियत संघ के वेनेरा मिशन के साथ वीनस की खोज शुरू हुई थी।
4. तब से लेकर अब तक विभिन्न देशों द्वारा शुक्र ग्रह को उसके ऑर्बिटर, लैंडर मिशन और वायुमंडल का पता लगाया जा चुका है लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है।

बॉडी के बाहर ऐक्शन में ह्यूमन ब्रेन

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने लैब में एक मिनि वर्किंग ब्रेन डिवेलप किया है। इस ब्रेन की मदद से अल्जाइमर और स्किट्सफ्रीनिया जैसी बीमारियों की स्टडी की जाएगी। लैब में तैयार किया गया यह ब्रेन डिश गर्भ में पल रहे दो माह के बच्चे के ब्रेन की तरह है। सेल से बने इस तंत्रिका सर्किट से स्टेम सेल्स की मदद से भी कोशिकाओं का निर्माण किया गया है। ऐसा पहली बार संभव हुआ है, जब मानव मस्तिष्क को शरीर के बाहर क्रियाशील अवस्था में देखा जा सकता है।

क्या है

1. ब्रिटिश मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, इस तंत्रिका सर्किट में सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक छोटी बॉल में री-क्रिएट किया गया है। इनमें वह स्फीरॉइड सेल्स भी शामिल हैं, जिनका निर्माण स्टेम सेल्स की मदद से किया गया है।
2. शोध से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस शोध के जरिए सामान्यतौर पर होने वाला दिमाग का विकास देखने और समझने के नए रास्ते खुलेंगे।
3. वैज्ञानिक इस प्रयोग के जरिए मिर्गी और ऑटिज्म के कारणों का खासतौर पर पता लगाना चाहते हैं। वह उन स्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, जब दिमाग की सेल हाइपरऐक्टिव हो जाती हैं। साथ ही सार्यटिस्ट्स ने कुछ अबनॉर्मल सर्किट्स जैसे ऑटिज्म से रिलेटेड टिमोथी सिंड्रोम को डिवेलप किया है, जिसके जरिए दिमांग में आने वाली विसंगति का पता किया जाएगा और फिर इसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी।
4. शोध से जुड़े वैज्ञानिकों और स्टेनफॉर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दो अग्रमस्तिष्क सर्किट भी विकसित किए हैं। इसी कड़ी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक तकरीबन 9 महीने से ह्यूमन रेटिना डिवेलप करने का प्रयास कर रहे हैं।
5. पिछले हफ्ते ऐसी ही एक खबर यूएस से आई थी। इसमें कहा गया था कि यूएस रिसर्चर्स ने ब्रेन के उस मेन सेल को डिवेलप कर लिया है, जो चोट और बीमारी की स्थिति में त्वचा की कोशिकाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पहली बार जासूसी उपग्रह छोड़ेगी स्पेसएक्स

अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स सेना के लिए पहली लॉन्चिंग को तैयार है। इस लॉन्चिंग में सरकार के राष्ट्रीय जासूसी कार्यालय (एनआरओ) के लिए पेलोड के रूप में गोपनीय उपग्रह छोड़ा जाएगा। एनआरओ ही अमेरिका के जासूसी उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण करता है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

क्या है

1. लांच किए जा रहे पेलोड के नाम के अतिरिक्त कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसका नाम एनआरओएल-76 है। स्पेसएक्स का फाल्कन-9 रॉकेट फ्लोरिडा के केप केनवेरल स्टेशन से स्थानीय समयानुसार सुबह सात बजे इस पेलोड को लेकर उड़ेगा।
2. लॉन्चिंग के 10 मिनट बाद रॉकेट का बड़ा हिस्सा अलग होकर धरती पर वापस लैंड करेगा। स्पेसएक्स ऐसे रॉकेट बनाने की दिशा में अध्ययन कर रही है, जिसके हिस्सों को दोबारा प्रयोग में लाया जा सके।
3. उद्यमी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अब तक कई बार धरती और समुद्र पर तैरते प्लेटफॉर्म पर रॉकेट की सफल लैंडिंग को अंजाम दे चुकी है।

विविध

आइआइटी में छात्राओं के लिए अब 20 फीसद अतिरिक्त सीटें

देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थान आइआइटी में छात्राओं की तादाद बढ़ाने के लिए कोटा व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसे वर्ष 2018 के सत्र से लागू किया जाएगा। नई नीति के तहत छात्राओं के लिए देश भर के सभी आइआइटी में अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की जाएगी।

क्या है

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल, आइआइटी में छात्राओं की गिरती संख्या से चिंतित संयुक्त दाखिला बोर्ड (जैब) ने प्रोफेसर टिमोथी गोंजालवेज की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। इसे संस्थान में छात्राओं की तादाद बढ़ाने के तौर-तरीकों को लेकर सुझाव देने को कहा गया था।
2. समिति ने साल की शुरुआत में सभी आइआइटी में छात्राओं के लिए 20 फीसद अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। यह वृद्धि मौजूदा सीटों के अतिरिक्त होगी।
3. जैब की बैठक में सिफारिश को मंजूर कर लिया गया। एचआरडी के अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सीटों पर हर वर्ष फैसला किया जाएगा। इसे अधिकतम आठ वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। कोटे के तहत खाली सीट को महिला अभ्यर्थी से ही भरा जाएगा।

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांगों को खड़े होने से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजने के दौरान दिव्यांगों को खड़े होने से छूट दिया है। इससे पहले गत 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान- श्जन गण मनश से जुड़े एक अहम अंतरिम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का समर्थन किया।

विश्व धरोहर दिवस

18 अप्रैल को दुनियाभर में विश्व धरोहर दिवस (वर्ल्ड हेरिटेज डे) मनाया गया है। यह दिन दुनियाभर की स्मारकों और एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए खास होता है। हर साल इस अवसर पर एक थीम बनायी जाती है और इस साल यह दीर्घकालिक पर्यटन (सस्टेनेबल टूरिज्म) है। विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त स्थलों के महत्व, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरुकता फैलाने के मकसद से ही यह विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। दरअसल यह एक मौका है जब हम लोगों को बताएं कि हमारी ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए कितनी कोशिश हो रही है। साथ ही यह दिन यह भी बताता है कि हमारी यह धरोहरों को अब कितने रखरखाव की जरूरत है।

क्या है

1. विश्व धरोहर या विरासत सांस्कृतिक महत्व और प्राकृतिक महत्व के स्थल होते हैं। यह वह स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता और इन्हें बचाए रखने के लिए खास कदम उठाए जाने की जरूरत होती है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। कोई भी स्थल जिसे यूनेस्को समझता है कि यह मानवता के लिए जरूरी है। वहां का सांस्कृतिक और भौतिक महत्व है, उसे विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता दी जाती है।
3. दुनियाभर में कुल 1052 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 814 सांस्कृति, 203 प्राकृतिक और 35 मिश्रित हैं।
4. भारत में फिलहाल 27 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 35 विश्व धरोहर स्थल हैं।

सांस्कृतिक धरोहर स्थल

1. आगरा का किला (1983)
2. अजंता की गुफाएं (1983)
3. नालंदा महाविहार (नालंदा विश्वविद्यालय), बिहार (2016)
4. सांची बौद्ध स्मारक (1989)
5. चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क (2004)
6. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) (2004)
7. गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स (1986)
8. एलिफेंटा की गुफाएं (1987)
9. एलोरा की गुफाएं (1983)
10. फतेहपुर सीकरी (1986)
11. ग्रेट लिविंग चोल मंदिर (1987)
12. हम्पी में स्मारकों का समूह (1986)
13. महाबलिपुरम में स्मारक समूह (1984)
14. पट्टडकल में स्मारक समूह (1987)
15. राजस्थान में पहाड़ी किला (2013)
16. हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)
17. खजुराहो में स्मारकों का समूह (1986)
18. बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर (2002)
19. माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया (1999)
20. कुतुब मीनार और इसके स्मारक, दिल्ली (1993)
21. रानी-की-वाव पाटन, गुजरात (2014)
22. लाल किला परिसर (2007)
23. भीमबेटका के रॉक शेल्टर (2003)
24. सूर्य मंदिर, कोर्णाक (1984)
25. ताज महल (1983)
26. ला कॉर्ब्युएर का वास्तुकला कार्य (2016)
27. जंतर मंतर, जयपुर (2010)

शेक्सपीयर का आज जन्मदिन

ब्रिटिश कवि और लेखक विलियम शेक्सपीयर का आज (23 अप्रैल) जन्मदिन है। शेक्सपीयर का नाम आते ही हर कोई उनकी लिखी कहानियों, नाटकों और कविताओं के बारे में सोचने लगता है। लेकिन कम ही लोग को पता है कि वे एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने लंदन में उस समय का सबसे बड़ा ओपन एयर एम्फी थिएटर बनाया था, जिसका नाम ग्लोब थिएटर था। शेक्सपीयर की असली जन्म तारीख तो नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 के आसपास ही हुआ था। इसी तरह उनकी मृत्यु को लेकर भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते और माना जाता है कि उनका निधन अपने जन्मदिन के मौके पर ही 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। हम भारतीय तो शेक्सपीयर को और भी कम जानते हैं। हमारे लिए शेक्सपीयर अंग्रेजी को करीब 3 हजार नए शब्द देने वाला एक शख्स मात्र हैं। इसके अलावा ज्यादातर भारतीय शेक्सपीयर को उनके नाटकों पर आधारित फिल्मों के लिए ही जानते हैं। पश्चिमी जगत में शेक्सपीयर को काफी इज्जत की नजर से देखा जाता है। शेक्सपीयर की कहानियों, नाटकों, कविताओं और अंग्रेजी भाषा के लिए उनके योगदान को काफी

प्राकृतिक धरोहर स्थल

1. हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र (2014)
2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985)
3. केओलादेओ नेशनल पार्क (1985)
4. मानस वन्यजीव अभयारण्य (1985)
5. नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988)
6. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (1987)
7. पश्चिमी घाट (2012)

मिश्रित

1. कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान (2016)

शेक्सपीयर की कृतियों पर बॉलीवुड में बनीं ये फिल्में

1. कॉमेडी ऑफ एरर्स - भ्रांति बिलास (1963), दो दूनी चार (अंगूर) (1968)
2. ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम - 10 एमएल लव (2010)
3. हेमलेट - हैदर (2014)
4. मैकबेथ - मकबूल (2004)
5. ओथेलो - ओमकारा (2006)
6. रोमियो एंड जूलियट - इशक (2013), गोलियों की रासलीला राम-लीला (2014)

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

सराहा जाता है। हम भारतीय लोग शेक्सपीयर को मकबूल, ओमकारा और हैदर जैसी फिल्मों से जानते हैं।

अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बताकर बनाया वर्ल्ड रिकार्ड

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन को अंतरिक्ष में रहकर वर्ल्ड रिकार्ड बनाने पर बधाई दी है। पेगी ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताकर पूर्व में जैफ विलियम द्वारा बनाया गया रिकार्ड तोड़ दिया। पेगी वर्ष 2008 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडर बनी थीं। इस वर्ष 9 अप्रेल को एक बार फिर उन्होंने आईएसएस की कमान दोबारा संभीली थी। मार्च में उन्होंने 53 घंटे स्पेसवाक कर रिकार्ड बनाया था जो कि स्पेस में किसी महिला द्वारा बनाया गया एक रिकार्ड है। उन्होंने ऐसा कर भारतीय मूल की सुनिता विलियम्स का रिकार्ड तोड़ा था।

तीन तलाक विधि विरुद्ध प्रभावहीन व शून्य घोषित

मुस्लिम विधि अनुसार तीन तलाक का प्रावधान है, किंतु इसमें भी शर्तें हैं। इनके पालन के बिना यह तलाक विधि विरुद्ध, प्रभावहीन और शून्य हो सकता है। ऐसा ही फैसला एक प्रकरण में कुटुंब न्यायालय के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश शर्मा ने दिया है। बेगमबाग निवासी लियाकत खान की बेटी अर्शी का निकाह देवास के रेवाबाग खुर्शीद मंजिल के पीछे निवासी तौसिफ शेख के साथ 19 जनवरी 2013 को हुआ था। कुछ समय बाद पति द्वारा रुपयों की मांग की गई। इंकार करने पर पति मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करा दिया, जो विचाराधीन है। पति तौसिफ ने अदालत से कहा कि उसने 9 अक्टूबर 2014 को शाबिर शेख, अजहर व साजिद अली देवास के समक्ष मुस्लिम रीति-रिवाज अनुसार उज्जैन न्यायालय में अर्शी को मौखिक तलाक दे दिया था। इसके बाद उसने अर्शी को नोटिस देकर सूचित किया कि उक्त दिनांक को कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय उसने तीन बार बोलकर तलाक दे दिया है।

क्या है

1. उल्लेखनीय है कि तीन बार तलाक व्यक्ति जिसे देता है उसकी उपस्थिति भी जरूरी है। प्रकरण की विवेचना के दौरान न्यायालय ने कहा कि उक्त दिनांक को किस न्यायालय में और किस प्रकरण में पेशी थी और उस प्रकरण में अर्शी और तौसिफ मौजूद थे अथवा नहीं, ये प्रमाण पेश नहीं हुए हैं।
2. जिनके समक्ष तलाक देना बताया है, उनमें से भी किसी के कथन नहीं कराए गए हैं। नोटिस के पूर्व उसके परिवार के बीच कोई सुलहवार्ता भी नहीं हुई।
3. न्यायालय ने कहा कि तौसिफ द्वारा 9 अक्टूबर 2014 को अर्शी को दिया गया तलाक विधि विरद्ध प्रभावहीन और शून्य है।

अनजाने में धर्म का अपमान अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनजाने में या गलती से अगर कोई शख्स धर्म का अपमान कर बैठता है तो उसके खिलाफ मामला नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कानून की धारा 295A के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में इस सेक्शन के तहत आरोप साबित होने पर कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अनचाहे तरीके से, लापरवाही में या बिना किसी खराब मंशा के अगर धर्म का अपमान होता है या किसी वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं तो यह काम कानून की इस धारा के अंतर्गत नहीं आता।

क्या है

1. महेंद्र सिंह धोनी ने खुद पर लगे धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप के मामले में केस चलाए जाने को चुनौती दी थी। मामला 2013 का है, जब उन्हें एक बिजनस मैगजीन के कवर पेज पर 'भगवान विष्णु' के तौर पर दिखाया गया था।
2. सुप्रीम कोर्ट की ताजा राय से निश्चित तौर पर उन लोगों, खास तौर पर सार्वजनिक छवि वाले लोगों के हितों की रक्षा होगी, जो अक्सर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जानबूझकर निशाना बनाने वालों के शिकार हो जाते हैं।
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के मामले में इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट 2000 के सेक्शन 66ए को खत्म करके भी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स को बड़ी राहत दी थी।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 295। की सीमाओं को लेकर भी टिप्पणी की। बता दें कि कानून की यह धारा कहती है कि 'जानबूझकर दुर्भावना से भरी हुई हरकतों से धार्मिक भावनाओं को भड़काना या किसी वर्ग विशेष का धर्म या उसके धार्मिक विश्वास के आधार पर अपमान करना' अपराध के दायरे में आता है।
5. सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में एक फैसला दिया था, जिसके मुताबिक बिना गलत नीयत के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के मामले पर किसी शख्स पर सेक्शन 295। का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
6. यह शीशे की तरह साफ है कि सेक्शन 295ए के जरिए हर मामले में सजा नहीं दी जा सकती। इसके तहत किसी भी काम को धर्म या किसी वर्ग विशेष की धार्मिक आस्थाओं का अपमान या अपमान की कोशिश नहीं माना जा सकता।
7. इस ऐक्ट के जरिए सिर्फ उनको सजा दी जाती है, जो जानबूझकर या गलत भावना के तहत वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि 1957 में संविधान बेंच के फैसले से भी इस बात की पुष्टि होती है।
8. ताजा मामला 2016 का है, जब कमीडियन किकू शारदा को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में गिरफ्तार होना पड़ा था।
9. इससे पहले, सितंबर 2014 में सलमान खान पर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था।
10. सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन के फैशन शो में एक मॉडल ने रैंप वॉक के दौरान जो टीशर्ट पहनी थी, उस पर अरबी में लिखे शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
11. इसके अलावा, ऐक्टर आमिर खान के खिलाफ उनकी फिल्म पीके को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीके में उनके भगवान शिव के गेटअप को लेकर आपत्ति की गई थी।

पृथ्वी मातृ को बचाने के लिए भारत की पहल

संयुक्त राष्ट्र 22 अप्रैल को एक विशेष दिवस के रूप में पृथ्वी मातृ दिवस मनाता है। 1970 में 10000 लोगों के साथ प्रारंभ किये गये इस दिवस को आज 192 देशों के एक अरब लोग मनाते हैं। इसका बुनियादी उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा और भविष्य में पीढ़ियों के साथ अपने संसाधनों को साझा करने के लिए मनुष्यों को उनके दायित्व के बारे में जागरूक बनाना है। 2017 के विषय 'पर्यावरण और जलवायु साक्षरता' का उद्देश्य पृथ्वी माँ की रक्षा के लिए आम लोगों में इस मुद्दे के प्रति जानकारी को और सशक्त बनाया और उन्हें प्रेरित करना है।

क्या है

1. आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल) के मुताबिक भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मामले में सबसे कमजोर है जो स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
2. जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के समाधान के लिए भारत ने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी): जलवायु न्याय की दिशा में कार्य करने' के उद्देश्य से एक व्यापक योजना विकसित की है।
3. इस दस्तावेज में इस मुद्दे के समाधान के लिए समग्र रूप से अनुकूलता के घटक, शमन, वित्त, हरित प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है।
4. इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन के दौरान, विकासशील देशों के लिए स्थायी विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के अधिकार के लिये न्यायोचित कार्बन उपयोग का भी आहवान किया गया है।
5. 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई पहलों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा हेतु 3500 मिलियन या 56 मिलियन अमरीकी डॉलर से 'राष्ट्रीय अनुकूलन कोष' के गठन से नीतियों की पहल की जायेगी।
6. इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु वायु, स्वास्थ्य, जल और सतत कृषि की पुनः परिकल्पना के अतिरिक्त अभियान के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाही (एनएपीसीसी) के अतंर्गत राष्ट्रीय अभियानों को फिर से प्रारंभ करना है।
7. 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 35 गीगावॉट (गीगा वाट) से 175 गीगावॉट तक बढ़ाने के द्वारा स्वच्छ और हरित ऊर्जा का निर्माण शमन रणनीतियों में शामिल है। सौर ऊर्जा में पांच गुना वृद्धि के साथ इसे 1000

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

गीगावॉट तक बढ़ाना के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन के अतिरिक्त देश भर में बिजली पारेषण और वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पावर ग्रिड को भी विकसित करना है। 10 प्रतिशत ऊर्जा खपत को बचाने हेतु ऊर्जा की खपत को रोकने के लिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

8. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंर्तगत 22.66 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं इससे न सिर्फ 11776 करोड़ रुपये की बचत होगी बल्कि यह प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में भी 24 मीट्रिक टन की कमी लाएगी।

9. स्वच्छ भारत मिशन की एक और रणनीति शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने की पहल भी है। इसी तरह देश भर में 816 सीवेज उपचार संयंत्रों में पुर्नचक्रण के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करके प्रतिदिन 23,277 मिलियन लीटर पानी को स्वच्छ बनाना एक और पहल है।

नया प्रस्ताव क्यों है चिंताजनक

1. बेहद कुशल पेशेवरों को मिल सकेगा यह वीजा
2. कंप्यूटर प्रोग्रामर कुशल पेशेवरों की सूची से बाहर हो चुके हैं। इससे भारतीय आईटी कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका
3. अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वालो की मिलेगी तवज्जो

एच-1बी वीजा का मुद्दा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रोस के समक्ष एच-1बी वीजा के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। साथ ही उन्होंने अधिक कुशल भारतीय पेशेवरों की अमेरिका में महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। ट्रंप प्रशासन में पहली बार दोनों देशों के बीच कैबिनेट स्तर की बैठक आयोजित हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रोस ने जेटली से कहा कि इस मामले की समीक्षा की जा रही है और अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

क्या है एच-1बी वीजा

इसके तत्काल योजना के तहत 15 दिन में 1225 डॉलर का प्रीमियम चुकाकर वीजा हासिल किया जा सकता है। इसके बिना यह वीजा पाने में औसतन 3 से 6 महीने लगते हैं। अमेरिका ने इस प्रीमियर प्रोसेसिंग पर 6 महीने की रोक लगा दी है।

क्यों है विरोध

1. अमेरिका में बड़े पैमाने पर एच-1बी वीजा का विरोध इसलिए होता रहा है क्योंकि उनका मानना है कि कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल करती हैं और आम कर्मचारियों को भी यह वीजा देती है।
2. 2013 में भारतीय कंपनी को ऐसे ही एक मामले में 25 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। ओबामा सरकार में भी इसकी फीस 2000 डॉलर से बढ़ाकर 6000 डॉलर कर दी गई थी, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था।

भारतीयों का दबदबा

1. 85,000 पेशेवरों को हर साल यह वीजा दिया जाता है।
2. 75 फीसदी भारतीय होते हैं इसमें।
3. 3 लाख के करीब भारतीय एच-1बी वीजा पर अमेरिका में।
4. वीजा आवेदन करने के मामले में शीर्ष-10 में शामिल विप्रो, इंफोसिस और टीसीएस।

वीआईपी कल्चर खत्म

वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. गाड़ियों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इसके तहत गाड़ियों में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर एक मई से रोक होगी. कोई भी व्यक्ति या गाड़ी लाल बत्ती नही लगाएंगे. इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव होगा।

क्या है

1. सरकार के नए फैसले के मुताबिक ना केंद्र में, ना राज्य में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पायेगा. जो प्रावधान ये अधिकार देता है वही कानून की किताब से हटा दिया गया है. हालांकि, इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियों को नीली बत्ती के इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा।
2. केंद्र और राज्य सरकार के पास किसी को कोई छूट देने का अधिकार नहीं होगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

3. देश में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
4. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी और साफ किया कि एक मई से देश में कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट से इसका प्रावधान ही पूरी तरह से हटा लिया गया है. जेटली ने कहा कि इसका कोई अपवाद नहीं है।
5. इसे फैसले के बाद नितिन गडकरी ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेस के लिए ही लाल बत्ती का विकल्प दिया गया है।

101 साल की उम्र में जीता गोल्ड मेडल

वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में भारत की महिला धावक मन कौर ने 101 साल की उम्र में परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आयोजित स्पर्धा में मन कौर ने 100 मीटर रेस में यह मेडल जीता है। कौर ने अपने करियर में यह 17वां गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौर ने एक मिनट 14 सेकंड्स में यह दूरी तय की, जो उसेन बोल्ट के 64.42 सेकंड के रेकॉर्ड से कुछ सेकंड ही कम है। उसेन बोल्ट ने 2009 में 100 मीटर की रेस में यह रेकॉर्ड कायम किया था।

क्या है

1. मन कौर 101 साल की बड़ी उम्र के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर काफी तेजी से बढ़ती दिखाई दीं।
2. 25,000 प्रतिभागियों वाली इस स्पर्धा में 100 या उससे अधिक उम्र की कैटिगिरी में मन कौर अकेली धावक थीं।
3. न्यूजीलैंड के मीडिया में 'चंडीगढ़ का आश्चर्य' कही जा रहीं मनकौर के लिए इस स्पर्धा में भाग लेना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था।
4. मनकौर को उनके बेटे ने गुरदेव सिंह ने इंटरनैशनल मास्टर्स सर्किट से जुड़ने का सुझाव दिया था। इससे पहले उनका खेलों को प्रति कोई अनुभव नहीं था। मेडिकल चेक-अप में ऑल क्लियर घोषित किए जाने के बाद कौर ने अपने बेटे के साथ अब तक दुनिया भर में एक दर्जन के करीब स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। अपने मेडलों की संख्या को 20 तक पहुंचाने के लिए कौर ऑकलैंड में 200 मीटर रेस, दो किलोग्राम गोला फेंक और 400 ग्राम भाल फेंक स्पर्धा में भी हिस्सा लेना चाहती हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के 72 साल बाद

72 साल पहले हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्व सोवियत संघ और नाजियों के बीच ऐतिहासिक बर्लिन की जंग की याद 23 अप्रैल फिर ताजा हो गई। मॉस्को के कुबिन्का स्थित पेट्रिओट पार्क में राइकस्टैग की प्रतिकृति बनाई गई और 10 देशों के 1200 सैनिकों ने इसे आग के हवाले कर जीत का उत्सव मनाया। मालूम हो, बर्लिन की जंग 1945 में 16 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चली थी।

ऐसा था द्वितीय विश्व युद्ध

1. द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। इसमें लगभग 70 देशों की थल-जल-वायु सेनाओं ने भाग लिया। 1939 से 1945 के बीच करीब 34 लाख बम गिराए गए। यानी प्रतिमाह औसतन 27,700 बम।
2. अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध में 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ। तब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इस युद्ध में विश्व दो भागों मे बंटा हुआ था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र।
3. युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया। यह मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के दौरान ही भारतीय धार्मिक प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक का प्रयोग नाजी

क्या है राइकस्टैगॉ

1. राइकस्टैग शब्द का इस्तेमाल जर्मन की संसद के लिए इस्तेमाल होता है। बर्लिन में स्थित इस राइकस्टैग इमारत को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आग के हवाले कर दिया गया था।
2. 1854 में बनी इस इमारत में 1933 तक संसद रही। इसके बाद लगाई गई आग में यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
3. रूस ने हाल ही में मॉस्को के मिलिट्री थीम पार्क में राइकस्टैग की प्रतिकृति भी बनाई थी, ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना जाग सके।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

सेना ने किया। इसमें 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जानें गई क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार तथा परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल शामिल है (जिसकी वजह से युद्ध के अंत मे मित्र राष्ट्रों की जीत हुई)। इसी कारण यह मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था।

4. भारत भी था शामिल दूसरे विश्वयुद्ध के समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाजी जर्मनी के विरद्ध 1939 में युद्ध की घोषणा कर दी।
5. ब्रिटिश राज (गुलाम भारत) ने एक लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भेजे। इन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन धुरी शक्तियों के विरद्ध युद्ध लड़ा। सभी देसी रियासतों ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि दी।

अमेरिका की मोस्ट वांटेड सूची में भारतीय

एजेंसी अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में 26 वर्षीय भारतीय भद्रेश कुमार चेतनभाई पटेल का नाम भी शामिल किया है। उस पर पत्नी की हत्या का आरोप है। एफबीआई ने उसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने वाले को एक लाख डॉलर (करीब 65 लाख रपए) देने की घोषणा की है।

क्या है

1. एफबीआई ने टॉप 10 भगोड़े अपराधियों की नई सूची की जानकारी दी। जांच एजेंसी ने बताया कि गुजरात निवासी पटेल पत्नी पलक (21) के साथ अमेरिका आया था। दोनों मैरीलैंड में हनोवर स्थित एक रेस्तरां में रात के शिफ्ट में काम करते थे। यह रेस्तरां पटेल के एक रिश्तेदार का था। 12 अप्रैल 2015 को पलक रेस्तरां की रसोई में मृत मिली थी।
2. एफबीआई ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें पटेल पलक के साथ रसोई में एक रैक के पीछे जाता दिखाई देता है। बाद में वह वहां से अकेले वापस लौटता है और कैमरे की जद से बाहर हो जाता है। एफबीआई ने कहा डे चाकू से कई बार हमला करने वाले पटेल को हथियारबंद और बेहद खतरनाक माना जाना चाहिए।
3. जांच एजेंसियों का अनुमान है कि पटेल यहां अपने किसी रिश्तेदार के साथ रह रहा होगा या संभवत: कनाडा भाग गया होगा। कनाडा से उसके भारत लौट जाने की भी आशंका है। एजेंसी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

IT क्षेत्र के 95% इंजिनियर जॉब के लायक नहीं: स्टडी

आईटी और डेटा सायेंस ईकोसिस्टम में भारत के इंजिनियर्स टैलंट के मामले में पिछड़ते दिख रहे हैं। एक सर्वे में सामने आया है कि देश के 95 प्रतिशत इंजिनियर सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट से जुड़ी नौकरियों के लिए काबिल ही नहीं हैं। रोजगार आकलन से जुड़ी कंपनी 'ऐस्पायरिंग माइंड्स' द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया कि लगभग 4.77 प्रतिशत उम्मीदवार ही प्रोग्रैम के लिए सही लॉजिक लिख सकते हैं, जो कि प्रोग्रैमिंग जॉब की न्यूनतम आवश्यकता है।

क्या है

1. आईटी संबंधित कॉलेजों की 500 ब्रांचों के 36,000 से ज्यादा छात्रों ने ऑटोमेटा को चुनाव दो तिहाई छात्र सही-सही कोड भी नहीं डाल सके। स्टडी में सामने आया कि जहां 60 प्रतिशत उम्मीदवार सही से कोड नहीं डाल पाए, वहीं 1.4 प्रतिशत ही ऐसे निकले, जिन्होंने सही कोड डालने में महारत हासिल है।
2. ऐस्पायरिंग माइंड्स के सीटीओ व को फाउंडर वरुण अग्रवाल कहते हैं, 'प्रोग्रैमिंग स्किल की यह कमी देश के आईटी सिस्टम को खासा प्रभावित कर रही है। भारत को इसमें और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।'
3. स्टडी में कहा गया कि प्रोग्रैमिंग के एक्सपर्ट्स की कमी, उम्मीदवारों तक उनका सही ढंग से न पहुंचना रोजगार की खाई पैदा कर रहा है, वहीं प्रोग्रैमिंग के अच्छे टीचर्स और एक्सपर्ट प्रोग्रैमर्स क्षेत्र में शानदार सैलरी उठा रहे हैं।
4. टिअर 1 और टिअर 3 के कॉलेजेस के बीच प्रोग्रैमिंग स्किल की गुणवत्ता में 5 गुना तक का अंतर देखने को मिलता है। 100 टॉप कॉलेजस के 69 प्रतिशत छात्र सही कोड डालने में सक्षम हैं, बाकी कॉलेजेस के छात्रों का इस मामले में आंकड़ा 31 प्रतिशत ही है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

युद्ध की आशंका के बीच पहुंची US सबमरीन

उत्तर कोरिया द्वारा फिर परमाणु परीक्षण की आशंकाओं के बीच अमरीका की एक पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के मुताबिक 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और 60 विशेष सैन्यबलों से लैस ये परमाणु पनडुब्बी बुसान बंदरगाह पहुंची है। यह अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस यूएसएस मिशीगन सबमरीन विमानवाहक युद्धपोत कार्ल विंसन के साथ आ रहे जंगी जहाजों के बेड़े के साथ जुड़ जाएगी।

क्या है

1. दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया में कोई असामान्य गतिविधी नहीं देखी गई है। इस बीच उत्तर कोरिया ने वोनसान शहर के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। एक बयान में दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया की सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
2. इस बीच उत्तर कोरिया ने अपनी सेना का 85वां स्थापना दिवस मनाया। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास किया है।
3. गौरतलब है कि हाल के कुछ समय में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध होने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। तनाव के बीच दोनों ओर से लगातार बयानबाजी भी जारी है। यही वजह है कि विशेषज्ञों को अब दोनों देशों के बीच लड़ाई का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है।
4. उत्तर कोरिया ने 16 अप्रैल को एक नाकाम बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया था जिसके बाद अमरीकी उप-राष्ट्रपति माइक पेंस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया राष्ट्रपति ट्रंप के धैर्य की परीक्षा न ले तो अच्छा होगा।

'चार्ली एब्दो' केस में मिली बड़ी कामयाबी

'चार्ली एब्दो' कार्यालयों और पेरिस में एक सुपरमार्केट पर 2015 के हमलों के लिए हथियार उपलब्ध कराने के लिए दस लोगों को फ्रांस और बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है। पेरिस अभियोजक के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस कार्रवाई में 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।

क्या है

1. 7 जनवरी, 2015 को हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जांच के ढांचे के तहत ऑपरेशन शुरू किया गया था।
2. चेरिफ और सैद कौआची दो भाइयों ने व्यंग्यपूर्ण साप्ताहिक समाचार पत्र 'चार्ली एब्दो' के कार्यालयों में घूसकर संपादक स्टीफन चारबोनियर समेत 12 लोगों की हत्या कर दी थी।
3. उसके दो दो दिन बाद, कौआची भाइयों के दोस्त अमेडी कॉलीबैली ने पेरिस में कोषेर सुपरमार्केट में चार लोगों की हत्या कर दी थी, इससे पहले कि उसे सुरक्षा बलों द्वारा गोली मारकर उनका एनकाउंटर किया जाता।
4. फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर कॉलीबैली को हथियारों की डिलवरी करने में शामिल थे।

आजाद हिंद मुस्लिम के गठन की मांग

नागालैंड में कोहिमा जिले के रुजाझो गांव में आयोजित दो दिवसीय सेमिनार में देश भर से आए स्कॉलर और शोधार्थियों ने अपनी विभिन्न मांगें रखीं। कोहिमा का युद्ध तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके प्रभाव पर आयोजित इस दो दिवसीय सेमिनार में जाने माने स्कॉलर, शोधार्थी और प्रोफेसर ने रुजाझो गांव को राष्ट्रीय विरासत गांव के रुप में घोषित करने की मांग की क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गांव का दौरा किया था। इसके अलावा उन्होंने आजाद हिंद मुस्लिम संगठन का गठन करने की भी मांग की।

क्या हुआ

1. सेमिनार में कहा गया कि इस जगह से नेताजी सुभाष चंद्र से जुड़े सारे अवशेष (हथियार, यूनिफॉर्म, झंडे) जिसका आईएनए ने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आजाद हिंद की मुद्रायें, किताबें और फिल्मों को सुरक्षित कर डिस्प्ले किया जाना चाहिए।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

2. आईएनए के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जो रुट अपनाया गया था वो नागालैंड के जेस्सामी, संघशक, संग्न्यु, सहपाओ, लाहे, रुजाझो, चोसीजू, विस्मेमा और माओ जैसे क्षेत्र हैं।
3. इन्हें शहीद स्मारक बनाया जाना चाहिए। बताया जाता है कि ये वो स्थल हैं जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी।
4. इन स्कॉलर ने राज्य और केंद्रीय सरकारों के समक्ष ये मांगे रखीं कि नागालैंड और मणिपुर में आईएनए के कामों के इतिहास का पता लगाने के लिए सक्षम विद्वानों द्वारा गंभीर शोध कर इसे भारतीय जनता के लिए प्रकाशित किया जाना चाहिए।
5. मालूम हो कि सेमिनार, फुत्सेरो गवर्नमेंट कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल डेवलपमेंट सोसाइटी और नागालैंड चकसंग स्टूडेंट युनियन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था।

अब इंटरनेट पर छा जाएगी हिंदी

एक नए अध्ययन में हिंदी के संदर्भ में यह उत्साहजनक संकेत सामने आए हैं। माना जा रहा है कि 2021 तक भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 53.6 करोड़ होगी। इनमें से 38 प्रतिशत यानी बीस करोड़ से अधिक हिंदी यूजर होंगे। दूसरे नंबर पर मराठी भाषा (5.1 करोड़) होगी। यह कुल इंटरनेट यूजरों का नौ प्रतिशत होगा। हिंदी और मराठी के बाद बंगाली (4.2 करोड़), तमिल (3.2 करोड़), तेलुगु (3.1 करोड़) और गुजराती (2.6 करोड़) का नंबर आएगा।

क्या है

1. भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2011 में यह संख्या 4.2 करोड़ थी तो 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 23.4 करोड़ हो गया।
2. अगले चार साल में यह संख्या 53 करोड़ से अधिक हो जाएगी। यानी पांच साल में दोगुने से अधिक। शोध के अनुसार अगले पांच सालों में हर दस नए इंटरनेट यूजरों में से नौ भारतीय भाषाओं वाले होंगे।
3. 2021 तक करीब 52 प्रतिशत आबादी की होगी इंटरनेट तक पहुंच।
4. अगले पांच साल में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 17.6 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान।
5. सितंबर से दिसंबर 2016 में मोबाइल डेटा की लागत में 96 प्रतिशत तक की कमी।
6. 2019 तक छह करोड़ ग्रामीण घरों तक डिजिटल साक्षरता पहुंचने की संभावना।
7. भारतीय भाषाओं में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में 99 प्रतिशत लोग मोबाइल के जरिये इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।
8. कुल मिलाकर भारत में 78 प्रतिशत इंटरनेट यूजर मोबाइल के जरिये वेब एक्सेस करते हैं।
9. 148 प्रतिशत इंटरनेट यूजर मानते हैं कि स्थानीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट इंग्लिश की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है।

आधुनिक 'सिल्क रोड' का यात्रा पूरा

चीन को सीधे ब्रिटेन से जोड़ने वाले रेलवे रूट पर पहली मालगाड़ी शनिवार को लंदन से चीन के पूर्वी शहर यिवु पहुंची। दुनिया के इस दूसरे सबसे लंबे रूट पर मालगाड़ी ने 12 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। मालगाड़ी का ये सफर इस लिहाज से अहम है क्योंकि चीन ने हाल में पश्चिमी यूरोप से आधुनिक 'सिल्क रोड' रूट के जरिए व्यापार बढ़ाने की कोशिशें तेज की है।

क्या है

1. दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक देश चीन ने 2013 में श्वन बेल्ट, वन रोडश की रणनीति को लॉन्च किया था। उसके बाद से ही उसने इंफ्रस्ट्रक्चर पर अरबों रुपये खर्च किया है।
2. लंदन से चीन पहुंची पहली मालगाड़ी में व्हिस्की, बेबी मिल्क, फार्मासूटिकल्स और मशीनरी से जुड़े सामान थे।
3. ये मालगाड़ी 10 अप्रैल को लंदन से रवाना हुई और फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस और कजाकिस्तान होते हुए 20 दिनों बाद चीन के पूर्वी जेजांग प्रांत के यिवु शहर पहुंची। यिवु छोटे उपभोक्ता सामानों का एक बड़ा थोक बाजार है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)

4. नया रूट रूस के मशहूर ट्रांस-साइबेरियन रेलवे से भी लंबा है लेकिन यह 2014 में बने चीन-मैड्रिड लिंक से करीब 1000 किलोमीटर छोटा है। लंदन 15वां शहर है जिसे चीन सरकार द्वारा संचालित चाइना रेलवे कॉर्पोरेशन की तरफ से नये फ्रेट नेटवर्क लिंक से जोड़ा गया है। चाइना रेलवे कॉर्पोरेशन का दावा है कि उसकी सेवा एयर ट्रांसपोर्ट से सस्ती है और नौ-परिवहन से तेज है।
5. लंदन से यिवु तक समुद्री मार्ग से सामान लाने या जाने की तुलना में रेल रूट से 30 दिन कम समय लगता है। हालांकि पायलट रन में 2 दिन ज्यादा लगे हैं क्योंकि 18 दिनों में सफर पूरा होने की उम्मीद थी। यिवु सरकार के मुताबिक मालगाड़ी की क्षमता सिर्फ 88 शिपिंग कंटेनरों की है जबकि कार्गो शिप की क्षमता 10 हजार से 20 हजार कंटनेर की होती है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL)